04 - म्यांमार में भारत की नई कूटनीतिक परीक्षा

05 - बारिश नहीं, हमारी तैयारियों की परीक्षा है मानसून

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 23 जून, 2026

06 - नवाचार, सतत विकास एवं वैश्विक साझेदारी के माध्यम से भविष्य का...

07 - 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर विदिशा में उमड़ा जनसैलाब

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 291, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

'एक रात वे सूचना देते
हैं- बीमा करा लिया है
वे बच्चों को प्यार
करना चाहते हैं
लेकिन अनायास ही वे
बच्चों को डाँटने लगते हैं
कभी-कभी वे नाकुछ
बात पर ठहाका लगाते हैं
हम देखते हैं उनके दाँत
पीले पड़ने लगे हैं
धीरे-धीरे झुर्रियाँ
उन्हें घेर लेती हैं
वे अपनी ही खंदकों,
अपने ही बीहड़ों में
छिपना चाहते हैं
यकायक वे किसी कंदरा,
किसी तंद्रा में चले जाते हैं
और किसी को भी पहचानने
से इंकार कर देते हैं।'

- कुमार अंबुज

प्रसंगवश

टीएमसी का पतन भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी चेतावनी है

आशुतोष

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का पतन भारतीय लोकतंत्र और क्षेत्रीय अस्मिता के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अस्तित्व बचाने के लिए क्या विपक्ष 1970 की तरह एकजुट होने का कड़ा फैसला लेगा?

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाना भारतीय राजनीति में एक बड़े अपशकुन का इशारा है। कहने को ये सिर्फ एक पार्टी का मिटना है, एक नेता का गिरना है, हकीकत में ये भारत की बड़ी तेज़ी से बदलती राजनीति का संकेत है। ये इस बात का संकेत है कि सत्ता किसी बहुत बड़े बदलाव का इशारा कर रही है और लोग उसे बस राजनीति के एक तिकड़म की नज़र से ही देख रहे हैं। ये बदलाव भारत की राजनीति में कायरों की जमा होती फौज का इशारा है, ये भारत की राजनीति से नैतिकता का हवा में ग़ायब होने का इशारा है। ये राजनीति के पूरी तरह शक्ति आधारित होने का भी इशारा है।

भारत की राजनीति में पहले भी बदलाव हुए हैं। पहले भी लोकतंत्र पर ख़तरे के बादल मँडराए हैं, राजनीति नाउम्मीद हुई थी, आशंकाओं ने पूरे समाज को हलकान कर दिया था, लेकिन तब सत्ता इस कदर शक्ति आधारित नहीं हुई थी। आपातकाल लगा था, लेकिन लोकतंत्र को लेकर आवाज़ें पूरी तरह से ख़ामोश नहीं हुई थीं। चुनाव के बाद जब इंदिरा गांधी हारी थीं, तो उनको हराने वाले असली नायक जयप्रकाश नारायण इंदिरा से मिलकर रोये थे। वो चिट्ठियाँ अपनी इंदू को देने गये थे जिनके बारे में जयप्रकाश नारायण को ये डर था कि कहीं वो सरकार के हाथ न लग जाये और वो उसका बेजा इस्तेमाल न करे। आज राजनीति में ये दस्तूर ख़त्म हो गया है। सत्ता और विपक्ष के बीच लोकतंत्र का जो पुल था वो टूट चुका है। आज दोनों ही सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है, वे एक दूसरे के शत्रु हैं, उफनती नदी के दो किनारे जो कभी नहीं मिलेंगे। जबकि लोकतंत्र आपसी मिलन का नाम है।

तृणमूल वही पार्टी थी जिसे चार मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले एक ऐसी नेता चला रही थी जो संघर्ष की प्रतीक थी, जिसने लेफ़्ट फ्रंट के 34 साल के शासन को ध्वस्त किया था, जो पंद्रह साल की मुख्यमंत्री थी और जिसे एक समय प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी देखा जाता था। आज वो ममता बनर्जी एक असहाय नेता हैं जिनके अपने साथियों ने पीठ में छुरा घोंपा है। ममता के गिरने का अर्थ है विपक्ष की एक बेहद मज़बूत दीवार का ढह जाना और ये संदेश फैलना कि अगर ममता की पार्टी ख़त्म हो सकती है तो फिर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी बचेगी नहीं। और अब सबसे बड़ा ख़तरा समाजवादी पार्टी पर मंडरा रहा है।

यूपी में अगले कुछ महीनों में चुनाव है। ये वो प्रदेश है जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिये जीत का मार्जिन इतना कम हो गया था कि वो हार लगने लगी थी। बीजेपी का सबसे बड़ा गुरूर तब टूटा जब वो अयोध्या यानी फैजाबाद में भी लोकसभा का चुनाव हार गई। ऐसे में अटकलों का दौर है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को वो सबक सिखायेगी कि फिर वो कभी बीजेपी के सामने खड़ा होने की जुर्रत न करें। ये अकारण नहीं है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी यूपी में जीती तो फिर इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा।

ऐसे में बड़ा सवाल ये है विपक्ष क्या करे? वो अपनी पार्टी बचाये, लड़े या फिर बीजेपी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो जाये? ये भी सवाल है कि क्षेत्रीय दलों का क्या भविष्य है ? वो छोटी होती हैं तो उनको तोड़ना सबसे आसान है। पहले शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी के दो टुकड़े हुए और अब तृणमूल धराशायी। उड़ीसा में नवीन पटनायक के बावजूद बीजू जनता दल की नैया डगमगा रही है। बिहार में नीतीश को गद्दी से उतारा जा चुका है। यूपी में बीएसपी की हालत खस्ता हैं। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर समाप्ति के कगार पर है। अकाली दल का भविष्य अनिश्चित है। आम आदमी पार्टी दिल्ली गँवाने के बाद पंजाब बचाने के लिये जान लगा रही है।

आरजेडी ज़िंदा है लेकिन बेहद कमज़ोर है। असम गण परिषद, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, एनसीपी अजीत पवार, शिवसेना एकनाथ शिंदे, जैसे दल बीजेपी की दया पर आश्रित हैं। टीडीपी सरकार में है तो अभी फ़िलहाल सुरक्षित है लेकिन कब तक? वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस का क्या होगा, ये सवाल हवा में तैर रहा है।

क्षेत्रीय दलों को समझना चाहिये कि बीजेपी की विचारधारा क्षेत्रीय अस्मिता को मज़बूत भारत की दिशा में एक बाधा मानती है। वो एक एकीकृत शासन व्यवस्था की वकालत करती है यानी एक नेता, एक विधायिका और एक सरकार। दीन दयाल उपाध्याय भी एकात्म मानववाद में कह चुके हैं कि भारत के संविधान में बंग माता है, तेलुगु माता है, तमिल माता है, कन्नड़ माता है लेकिन भारत माता कहां है?

ऐसे में क्षेत्रीय दलों को ममता बनर्जी के प्रसंग के बाद नई रणनीति पर सोचना होगा। ये संकट उत्तरजीविता का संकट है यानी अस्तित्व बचाने का संकट है। राहुल गांधी यूं ही नहीं कह रहे हैं कि अब प्रतिरोध करना होगा।

विपक्ष को ये समझना होगा कि जैसे 1970 के दशक में जब असाधारण परिस्थिति बनने पर सारे विपक्षी दलों ने जनता पार्टी में खुद के विलय का फैसला लिया था, वो समय आ गया है। अकेले जीने का मतलब है पार्टी का खत्म हो जाना। ऐसे में दो रास्ते हैं। एक, कांग्रेस से निकले हुए दल कांग्रेस में समा जायें। तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस इस विकल्प के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे में उनका अस्तित्व भी बचा रहेगा और एक राष्ट्रीय पार्टी के टेंट में आने से राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल प्ले करने का मौक़ा भी रहेगा। दो, समाजवादी विचारधारा से निकले दल फिर से एक जनता दल बनाने का विचार कर सकते हैं। अलग अलग तो एक भी नहीं बचेगा। और फिर विस्तारित कांग्रेस के साथ विस्तारित जनता दल का अखिल भारतीय मोर्चा बन जाये।

ये विकल्प मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। अगर 1970 के मध्य में जनसंघ जैसी हिंदुत्ववादी पार्टी समाजवादी और कांग्रेस से टूटे धड़ों के साथ अपना अस्तित्व खत्म कर जनता पार्टी में समाहित हो सकती है तो आज के हालात में कांग्रेस और जनता दल से टूट कर अलग हुई पार्टियां क्यों नहीं ऐसा कर सकती हैं। क्या विपक्ष असाधारण फैसले करने को तैयार है?

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

लखनऊ की कोचिंग में आग

15 स्टूडेंट की मौत

- 10 के फंसे होने की आशंका, आग से बचने के लिए बाथरूम में छिपे थे बच्चे

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर एक तीन मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। इनमें ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। एक बच्चे ने पहले फ्लोर से कूद कर जान बचाई। लेकिन वह नीचे ग्रिल पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां मौके पर हैं। एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म आग बुझाने में लगी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी पहुंची है। फायरकर्मियों ने बिल्डिंग की पीछे की दीवार को तोड़ा है, जिसके जरिए शवों को बाहर निकाला जा रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, अभी भी करीब 10 लोग अंदर फंसे हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे हैं। करीब 14 एम्बुलेंस मंगवाई गई हैं। बिल्डिंग में बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लीनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी (कोचिंग) और हेड हॉपर स्टूडियो है, जिसमें गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है।

सीएम योगी दिए राहत और बचाव कार्य के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने व घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि घटना के वक्त कई बच्चे अंदर थे। आग लगी तो वह नीचे कूदने लगे। घटना से जुड़े कई फोटो और वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा

विकास कार्यों का जिला स्तर पर होगा प्रेजेंटेशन : मुख्यमंत्री

सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी और आवासों में ईको फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के उपयोग को करें प्रोत्साहित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर जिला मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रमों में जिलों के प्रभारी मंत्री, जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। समारोह स्थल पर विकास कार्यों और योजनाओं को जनसामन्य के सामने रखने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी, यह प्रेजेंटेशन एक तरह से विकास कार्यों के सोशल ऑडिट जैसा होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिला विकास समितियों का राजधानी भोपाल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जिला विकास समितियां विकास गतिविधियों के लिए शासकीय नियोजन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करने के लिए जिला विकास समितियां प्रयास करें।

जिलों के विकास सूचकांक स्थानीय परिस्थितियों पर हों आधारित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों के विकास सूचकांक स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अलग-अलग निर्धारित किया जाए। औद्योगिक पृष्ठ भूमि, कृषि आधारित व्यवस्था, वन क्षेत्र संपन्न जिलों के लिए विकास के सूचकांक अलग-अलग हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं का मकान बनाने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री के संबंध में जागरूक करने के लिए भी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रस्फुटन और नवाकुंर समितियों की रही सक्रिय सहभागिता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक एक लाख 37 हजार से अधिक छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रस्फुटन और नवाकुंर समितियों ने कुएँ, बावड़ी, तालाब, नदी घाट सफाई, जल संगोष्ठी और बावड़ी उत्सव जैसे आयोजनों में सक्रिय सहभागिता की। बैठक में बताया गया कि विमुक्त, घुमंतु और अर्द्ध-घुमंतु परिवारों के चिन्हाकंन और पंजीकरण के लिए जारी अभियान में अब तक पच्चीस हजार से अधिक परिवारों की जानकारी पोर्टल पर प्रविष्ट की जा चुकी है। प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी जारी है।

लाठी लेकर पहुंचे सैकड़ों बांग्लादेशी, सीमा पर तनाव

- भारत में घुसपैठ कराने के लिए बांग्लादेश ने चली नई चाल

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश-भारत सीमा पर तनाव बढ़ गया है। शनिवार को बांग्लादेश की तरफ से भारत में घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये अवैध घुसपैठिए थे जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने बांग्लादेश में भेज दिया था। बांग्लादेश ने इन लोगों को अपने इलाके में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बाद में बांग्लादेश के सीमा रक्षा बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने इन लोगों पर भारत में वापस जाने के लिए दबाव बनाया। रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 20 लोगों ने भारत में घुसने की कोशिश की, जिसे बीएसएफ ने वापस खदेड़ दिया। इसके बाद यह समूह फिर बांग्लादेश की तरफ जमा हुआ। इस बार उनके पीछे लगभग 1000 लोग थे, जिन्होंने अपने हाथों में लाठी-डंडे लेकर पहुंचे थे। इससे सीमा पर तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि बाद में समूह वापस लौट गया।

बांग्लादेशी घुसपैठियों की वापसी का विरोध

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अवैध बांग्लादेशियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की कोशिश में तेजी आई है। बांग्लादेश की सरकार ने इन कोशिशों पर आपत्ति जताई है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने इनका विरोध किया है। बांग्लादेश ने कहा है कि किसी भी तरह की वापसी तय प्रक्रियाओं के अनुसार ही होनी चाहिए। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने हाल ही में संसद को बताया कि 5 अगस्त 2024 से अब तक 2369 लोगों को भारत से बांग्लादेश में भेजा जा चुका है। इस दौरान बीएसएफ ने 183 लोगों को वापस भेजा है।

उद्धव के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल

4 साल में दूसरी टूट, शिंदे बोले- छक्का लगाया

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 9 में से 6 सांसद सोमवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। बागी सांसदों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उनके नंदनवन बंगले पर बैठक की। इसके बाद बागी सांसदों ने शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाला बदलने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने कहा- जब हमने विद्रोह किया था, तब शुरुआत में 40 विधायक थे और अब चौके नहीं, छक्के लग चुके हैं। 2022 में शिवसेना ने पार्टी को बचाने के लिए धनुष-बाण को बचाने के लिए विद्रोह किया था। अब दूसरा चरण शुरू हो गया है। हमारी लड़ाई बालासाहेब के विचारों के लिए है, इन विचारों को संरक्षित करने के लिए है, इसीलिए आज इन 6 सांसदों ने पार्टी ज्वाइन की है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 23 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

रोजी-रोटी की तलाश में निकले थे, घर लौटीं लाशें !

यूरिया लदे ट्रक ने मजदूरों को रौंदा, 3 महिलाओं समेत 6 की मौत, 18 आईसीयू में भर्ती

छिंदवाड़ा (नप्र)। छिंदवाड़ा-बैतूल नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पांच परिवारों की खुशियां छीन लीं। टेमनी खुर्द के पास मजदूरों से भरी एक पिकअप को पीछे से आ रहे यूरिया से लदे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार मजदूर सड़क पर दूर-दूर तक जा गिरे। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर घायल मजदूर दर्द से कराहते रहे और स्थानीय लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया।

सब्जी तोड़ने जा रहे थे मजदूर, रास्ते में हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार सभी मजदूर मछैरा गांव के रहने वाले थे। सोमवार सुबह वे रोजी-रोटी कमाने के लिए कन्हरगांव स्थित खेतों में सब्जी तोड़ने जा रहे थे। मृतक सावित्री वनके (31) के पति सुरेश सिंह ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे मजदूर पिकअप में सवार होकर निकले थे। वाहन में लगभग 20 से 25 मजदूर मौजूद थे। टेमनी खुर्द के पास पहुंचते ही पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे यूरिया से भरे ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसा इतना भीषण, चकनाचूर हो गया पिकअप

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का पिछला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। कई मजदूर वाहन से उछलकर सड़क पर जा गिरे। कुछ लोग वाहन के भीतर ही फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया।

मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजन को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में पांच लोगों की असमय मृत्यु पर गहन दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मृतकों के परिजन को चार-चार लाख रुपये, गंभीर घायलों को एक-एक लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा घायलों के निःशुल्क उपचार के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिजन को यह दुःख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेमनी खुर्द के पास एक ट्रक और पिकअप की भिड़त हो जाने से यह दुखद दुर्घटना हुई।

मृतकों में तीन महिलाएं शामिल

हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। प्रारंभिक जानकारी में चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन उपचार के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर पांच हो गया। मृतकों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। प्रशासन द्वारा मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

रोजी-रोटी की तलाश में निकले थे, घर नहीं लौटे

ग्रामीणों के अनुसार पिकअप में सवार अधिकांश लोग खेतिहर मजदूर थे, जो प्रतिदिन मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सोमवार सुबह भी वे काम की तलाश में घर से निकले थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। हादसे की खबर गांव पहुंचते ही मातम पसर गया। अस्पतालों में परिजनों की भीड़ जुट गई और कई परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक और क्षतिग्रस्त पिकअप को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में ट्रक की तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है तथा दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पड़ताल की जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

बिहार में ऐक्टर पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर हुआ हमला

● घर के बाहर बैठे थे, हमलावर ने अचानक कुल्हाड़ी से वार किया

गोपालगंज (एजेंसी)। बिहार के गोपालगंज में एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई विजेंद्र नाथ पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इस घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर किया गया है। घटना

बरौली थाना क्षेत्र के बेलसंड गांव की है। विजेंद्र नाथ तिवारी रविवार देर शाम अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान आरोपी राजेश साह आया और अचानक विजेंद्र पर वार किया। हमले में वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। विजेंद्र नाथ को तुरंत सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने हालत को देखते हुए उन्हें पटना एम्स रेफर कर दिया। आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की भारत को फिर से धमकी

● रक्षामंत्री बोले-जिस पल पानी पर खतरा लगा जंग कर देंगे

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तानी चैनल से बातचीत में आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है, तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में इस मामले में क्या नए घटनाक्रम हुए हैं, इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने संधि को निलंबित कर दिया था।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का इस्तीफा

● कहा-पार्टी को नहीं लगता मैं अगला चुनाव जिता सकता हूं

लंदन (एजेंसी)। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार को प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लेबर

पार्टी को नहीं लगता कि मैं अगले चुनाव में नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हूं। स्टार्मर का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब लेबर पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर लंबे समय से असंतोष बढ़ रहा था। हाल के महीनों में कई सांसदों और मंत्रियों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। स्थानीय चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन और गिरती लोकप्रियता ने भी उनके ऊपर दबाव बढ़ा दिया था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एंडी बर्नहैम उनके उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं।

फिर से आएगा

महिला आरक्षण बिल

● 2029 से पहले लोकसभा-विधानसभा सीटें बढ़ाने का है प्लान

ऐक्टिव हो गई मोदी सरकार, एससी-एसटी कोटे को भी फायदा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के मकसद से एक नए संविधान संशोधन को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। इस प्रस्ताव पर सरकार के उच्च स्तरों पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। प्रस्तावित कानून, जिसे संविधान (133वां संशोधन) बिल के तौर पर पेश किया जा सकता है, मोटे तौर पर विफल रहे संविधान (131वां संशोधन) बिल पर ही आधारित होगा। लेकिन यह परिसीमन से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें यह सुझाव दिए जाने की संभावना है कि 1971 की जनगणना पर आधारित मौजूदा अंतर-राज्यीय सीट

अनुपात में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि, राज्यों के भीतर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं 2011 की जनगणना के आधार पर फिर से तय की जा सकती हैं।

ड्राफ्ट लगभग तैयार, बदलाव भी संभव- सूत्रों के मुताबिक, ड्राफ्ट काफी हद तक तैयार है और इसमें आर्टिकल 55, 81, 82, 170, 330, 332 और 334ए में बदलाव की मांग की जा सकती है। प्रस्तावित कानून में सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा।

राज्यों के साथ लेते हुए किया जा रहा काम

सूत्रों का कहना है कि नए ढांचे का मकसद 2029 में इसे लागू करने की समय-सीमा को बनाए रखना है, साथ ही राज्यों की इस चिंता को भी दूर करना है कि प्रतिनिधित्व में उनका हिस्सा बदल सकता है। पता चला है कि इस ड्राफ्ट की रूपरेखा पर कई बैठकें हुई हैं, जिनमें हुई बैठक भी शामिल है। हालांकि, सरकार तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक उसे इसे पास कराने के लिए ज़रूरी संख्या का भरोसा न हो जाए। पहले वाले प्रस्ताव की तरह ही, इस बिल को भी दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी। एक सूत्र ने कहा कि सब कुछ संख्या पर निर्भर करता है जिससे संकेत मिलता है कि सरकार जरूरी समर्थन मिलने का भरोसा होने के बाद ही यह कानून लाएगी।

एससी-एसटी कोटे का भी प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है

सीटों की संख्या बढ़ने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ सकता है। मौजूदा सोच के अनुसार, लोकसभा में एससी सीटों की संख्या 84 से बढ़कर 136 और एसटी सीटों की संख्या 47 से बढ़कर 70 हो सकती है। आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने के अलावा, इस कवायद से सदन में अनुसूचित जातियों के लिए मौजूदा 15.46 के मुकाबले पूरे 16 फीसदी आरक्षण को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा। महिलाओं के लिए कोटा वर्टिकली (लंबवत) लागू होगा, जिसका मतलब है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए भी तय की जाएंगी। इसके अनुसार, प्रस्तावित 136 एससी सीटों और 70 एसटी सीटों में से लगभग एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं।

डॉ. मुखर्जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना जरूरी

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता और अखण्डता को दी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को निधन 23 जून 1953 को हुआ, जिसे राष्ट्रहित में दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान के रूप में देखा जाता है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में विशेष व्यवस्था के विरोध में आंदोलन किया था, उनका बलिदान राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक माना जाता है। डॉ. मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक, सांसद और दूरदर्शी राजनेता थे। डॉ. मुखर्जी ने वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने वैचारिक राजनीति और संगठन निर्माण पर बल दिया और राष्ट्रहित को दलगत राजनीति से ऊपर रखने का संदेश दिया। डॉ. मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगरीय निकायों के महापौर तथा नगरपालिका अध्यक्ष को मुख्यमंत्री निवास से वी.सी. के माध्यम से संबोधित कर यह निर्देश दिए।

जनसेवा का अभियान हो पखवाड़ा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का मानना था कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रेरित किया। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाना है। पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा मार्गों और उद्यानों का नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जा सकता है। इस प्रकार की पहल के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन, आवश्यक रूप से किया जाए तथा सक्षम स्तर से सभी स्वीकृतियां अवश्य ली जाएं। पखवाड़ा जनसेवा का अभियान होना चाहिए। पौधरोपण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। यह पखवाड़ा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने तथा सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूत करने का अवसर है।

मान गया रूठा मानसून, 15 दिन बाद आगे बढ़ा

● तेलंगाना के रास्ते छत्तीसगढ़ में एंट्री, झमाझम बारिश शुरू

राजस्थान में ओले गिरे, एमपी-यूपी में हीटवेव का अलर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। 15 दिन से छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अटके मानसून की दंतेवाड़ा के रास्ते में राज्य में एंट्री हो गई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम ने मानसून को आगे बढ़ने में मदद की है। इसके साथ ही बस्तर संभाग में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों में यह राज्य के बाकी जिलों को भी कवर कर लेगा। तमिलनाडु के थूथूकोडी में रविवार को बवंडर आया। पहले इसे टॉरनेडो बताया गया था। लेकिन आईएमडी ने सोमवार को पुष्टि करते हुए कहा कि थूथुकुडी की घटना लोकल कन्वेक्टिव वॉर्टेक्स यानी धूल का बवंडर थी। रविवार को मेघालय में भारी बारिश हुई। खासी हिल्स जिले के मॉसिनराम में 24 घंटे में 530 मिमी बारिश दर्ज की गई। यानी एक रात में यहां जितनी बारिश हुई, उतनी जोधपुर-बीकानेर में 6 महीने में होती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रविवार को ओले गिरे। वहीं, एमपी के 5 जिलों में आज हीटवेव का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में लू चल सकती है।

गर्मी से जूझ रहे 8 राज्य, विदर्भ में रात में भी लू चल रही- उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में तापमान 40-42 डिग्री के बीच है। तेलंगाना, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ अलग-अलग इलाकों में भी तापमान इसी रेंज में है। विदर्भ के 8 जिलों में लगातार गर्मी के कारण रातें भी गर्म हो रही हैं। यहां रात में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इधर, उत्तर प्रदेश का बांदा लगातार दूसरे दिन देश में सबसे गर्म रहा। यहां पारा 42.6 रिकॉर्ड किया

गया। इसके अलावा कानपुर, वाराणसी, बहराइच और प्रयागराज में भी पारा 42 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ।

- **देश में इतिहास का दूसरा सबसे सूखा जून बीत रहा-** देश में मानसून की बारिश के रिकॉर्ड के 126 साल के इतिहास में दूसरा सबसे सूखा जून बीत रहा है। 21 जून तक 57.4 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 42.2 फीसदी कम है। इससे पहले 2009 में पूरे जून में कोटे से 49 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी। इससे मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में खेती पर बुरा असर पड़ा था। हालांकि, मानसून दो हफ्ते बाद अब आगे बढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बना है, जो मानसून को छत्तीसगढ़ तक पहुंचाएगा। रविवार को मेघालय के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। खासी हिल्स जिले के मॉसिनराम में 24 घंटे में 530 मिमी बारिश दर्ज की गई। यानी एक रात में यहां जितनी बारिश हुई, उतनी 6 महीने में होती है।

56825 किलोमीटर क्षेत्र को मिलेगी ईएसए सुरक्षा

● पश्चिमी घाट में बड़ा बदलाव करेगी मोदी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र की मोदी सरकार 12 साल बाद पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों को विशेष पर्यावरणीय सुरक्षा मिलेगी। इसका मतलब है कि ऐसे इलाकों में खनन, बड़ी फैक्ट्रियां, थर्मल पावर प्लांट और कई तरह की औद्योगिक गतिविधियों पर रोक या कड़ी पाबंदी लग जाएगी। हालांकि, केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर सभी राज्य सहमत नहीं हैं। इसी वजह से केंद्र ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है।

अब सरकार उन राज्यों में ईएसए लागू करने की तैयारी कर रही है जहां इस पर सहमति बन चुकी है या बनने के करीब है। जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी घाट को भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। यह गुजरात से लेकर केरल तक फैली हुई है।

- **नए खनन प्रोजेक्ट, खदानें, पत्थर तोड़ने की परियोजनाएं रुकेंगी-** अगर किसी क्षेत्र को ईएसए घोषित कर दिया जाता है तो वहां नए खनन प्रोजेक्ट, खदानें, पत्थर तोड़ने की परियोजनाएं, रेत खनन, सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले रेड-कैटेगरी उद्योग और 20,000 वर्गमीटर या उससे बड़े निर्माण प्रोजेक्ट पर रोक लग जाती है। 2024 में जारी ताजा ड्राफ्ट के मुताबिक केंद्र सरकार 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ईएसए घोषित करना चाहती है। यह क्षेत्र छह राज्यों में फैला हुआ है।

सरकारी कर्मचारियों को बंगाल सरकार का तोहफा

नए बजट में 38 फीसदी डीए देने का किया ऐलान

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने सोमवार को भाजपा सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में कहा गया कि सरकार 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों को भरेगी और इसमें महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा विभाग के लिए फंड 5,713 करोड़ से घटाकर 2,165.42 करोड़ कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 4 लाख 30 हजार करोड़ के बजट में पूर्व सीएम ममता बनर्जी के समय शुरू हुई सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं (जैसे- अन्नपूर्णा योजना और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा) को जारी रखा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की मंत्रालय में समीक्षा की।

महाकाल की भस्म आरती के लिए नई व्यवस्था

एक मोबाइल नंबर से 3 माह में एक बार मिलेगी अनुमति ; प्रोटोकॉल वालों पर भी लागू

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए अब श्रद्धालु तीन माह में केवल एक बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे। यह व्यवस्था प्रोटोकॉल से आने वाले ऐसे मोबाइल नंबरों पर भी लागू होगी, जिनसे हर माह भस्म आरती की अनुमति ली जा रही है। हालांकि, मंदिर समिति का कहना है कि यह व्यवस्था पहले से लागू है, जिसे अब और प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

करीब दो वर्ष पहले तक श्रद्धालु भस्म आरती की बुकिंग 15 दिन पहले ऑनलाइन करवा सकते थे। इसके लिए मोबाइल नंबर से जुड़ा कोई विशेष नियम नहीं था। वर्ष 2024 में भस्म आरती की अनुमति को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के चलते तत्कालीन कलेक्टर नीरज सिंह ने

ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर से तीन माह बाद ही दोबारा अनुमति देने का निर्णय लिया था। यह व्यवस्था कुछ समय तक लागू रही, लेकिन बाद में बंद कर दी गई थी।

अब एक बार फिर भस्म आरती की अनुमति को लेकर मिल रही शिकायतों के चलते मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग तीन माह बाद ही दोबारा किया जा सकेगा। इस व्यवस्था को लागू भी कर दिया गया है। अब जो श्रद्धालु प्रोटोकॉल या अन्य माध्यमों से हर माह भस्म आरती की अनुमति लेकर दर्शन करने आते थे, उन्हें तीन माह बाद ही दोबारा अनुमति मिल सकेगी।

महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि यह व्यवस्था पहले से लागू है। इसे अब और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। अब एक ही मोबाइल नंबर का बार-बार उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

जनपरिषद का 37वां वार्षिक समारोह 23 जून को

दीपक वोहरा भी शिरकत करेंगे

भोपाल। अग्रणी सामाजिक संस्था जन परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीपी श्री एन के त्रिपाठी के अनुसार मंगलवार 23 जून को रवींद्र भवन में शाम चार बजे परिषद का 37वां वार्षिक समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में पूर्व एंबेसडर एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों के अग्रणी ज्ञाता श्री दीपक वोहरा, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना, एयर मार्शल श्री प्रमोद श्रीवास्तव एवं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अनुपम राजन जी को आमंत्रित किया गया है।

नगर निगम के ट्रक में आग

शार्ट सर्किट से केबिन में आग भभकी ; पानी की बॉटल लेकर दौड़े लोग

भोपाल (नप्र)। भोपाल के रायसेन रोड स्थित एलएनसीटी यूनिवर्सिटी गेट के सामने से गुजर रहे नगर निगम के ट्रक में अचानक आग लग गई। शार्ट सर्किट की वजह से केबिन के नीचे आग भभकी थी, जिसे कर्मचारी और लोग बॉटलों में भरे पानी से बुझाने दौड़े। बताया जाता है कि रविवार रात कंटेनरनुमा ट्रक आदमपुर कचरा खंती से लौट रहा था। जैसे ही यह एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने पहुंचा, केबिन में से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने उतरकर देखा तो केबिन के नीचे आग लगी हुई थी। आग बुझाने के लिए राहगीरों की मदद ली गई। एक गाड़ी में रखी पानी की बड़ी बॉटलों के जरिए आग बुझाने के प्रयास हुए, लेकिन वह काबू में नहीं आ पाई। कुछ ही देर में केबिन के साथ ट्रक के अगले टॉयर भी जल गए। करीब आधे घंटे तक दमकल भी मौके पर नहीं पहुंची।

तीन टुकड़ों में मिला 5 साल के बच्चे का शव

17 जून से लापता था ; परिजन को लगा पिता के पीछे-पीछे जंगल गया था

डिंडौरी (नप्र)। डिंडोरी में सोमवार को एक 5 वर्षीय बच्चे का शव तीन टुकड़ों में जंगल में मिला है। जानकारी के अनुसार बच्चा 17 जून से लापता था। पुलिस चार दिनों से तलाश कर रही थी।

करंजिया थाना क्षेत्र के तरेरा गांव निवासी इख्तियार खान जंगल में लकड़ी लेने गए थे। उनका बेटा इमरान सुबह सोकर उठा और पिता के पीछे जंगल की ओर चला गया। परिजन को लगा कि बच्चा पिता के साथ ही है।

पिता के साथ नहीं लौटने पर लापता होने का पता चला

इख्तियार लकड़ी लेकर घर लौटे और बेटे के बारे में पूछा, तब परिजन को उसके लापता होने का पता चला। उन्होंने पहले आस-पड़ोस में बच्चे की तलाश की, लेकिन जब वह नहीं मिला तो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एक टीम गठित कर जंगल और आसपास के गांवों में सर्चिंग अभियान चलाया। गुमशुदगी की खबर सोशल मीडिया पर भी प्रसारित की गई। सोमवार को गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर बच्चे का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की टीम भी घटनास्थल पर बुलाई गई है।

ऊर्जा मंत्री ने लगाई चौपाल

गुस्साए गांव वालों ने लगाए 'बिजली विभाग चोर है' के नारे

शिवपुरी (नप्र)। जिले के खोड़ स्थित धाय महादेव मंदिर परिसर में जन चौपाल में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने वीरा गांव के ग्रामीणों ने 'बिजली विभाग चोर है' के नारे लगाकर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।

शिकायतों का अंबार देख चौंक गए मंत्री: ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जिले के दौरे पर थे। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनने के लिए लगभग दो घंटे तक जन चौपाल लगाई। इस दौरान बिजली, सड़क, सीमांकन, हैंडपंप और पेंशन से जुड़ी करीब 200 शिकायतें प्राप्त हुईं।

ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप: जन चौपाल में वीरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई बिजली के खंभे और तार टूटकर खेतों में पड़े हुए हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने बारिश के मौसम में दुर्घटना की आशंका जताते हुए तत्काल समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि लापरवाही के चलते किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

तार जोड़ने के पैसे मांगे जाने का आरोप: ग्रामीण सुखेंद्र राय ने आरोप लगाया कि शासकीय कार्य के लिए विभाग के कर्मचारियों ने उनके घर का तार काट दिया था। जोड़ने के लिए पहले पिता से 1500 रुपए लिए गए। अब 21 दिन से तार टूटा पड़ा है और दोबारा जोड़ने के लिए 3 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। इस तरह की वसूली से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वीरा गांव के ग्रामीणों ने खुलेआम विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर बिजली कंपनी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए।

ग्रामीण सुखेंद्र राय ने आरोप लगाया कि सरकारी काम के नाम पर उनके घर का कनेक्शन काटा गया और जोड़ने के बदले पिता से 1500 रुपये ऐंठ लिए गए।

'काफिर कहने वाले भी हमारी बनाई सड़क पर चलते हैं'

1.25 करोड़ की सड़क के लोकार्पण में बोले कैलाश विजयवर्गीय

इंदौर (नप्र)। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आयोजित एक सार्वजनिक मंच से बड़ा बयान दिया है। रविवार को इंदौर के राजनगर इलाके में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ किया कि भाजपा सरकार ने कभी भी किसी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। विजयवर्गीय ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि कुछ लोग हमें 'काफिर' कहते हैं, तो उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि वे जिन सड़कों पर चलते हैं और जिन सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, वे सभी इसी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं।

सवा करोड़ की सड़क का हुआ लोकार्पण

यह पूरा कार्यक्रम राजनगर बड़ा कुआं से धार रोड तक करीब 1.25 करोड़ रुपये की लागत से बनी नई सड़क के उद्घाटन के सिलसिले में आयोजित किया गया था। इस दौरान मंच पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इस क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग मिल-जुलकर रहते हैं और सरकार ने बिना किसी सामाजिक या धार्मिक भेदभाव के यहाँ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया है।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री द्वारा कही गई मुख्य बातें

- लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी जैसी जनहितैषी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग की महिलाओं को मिल रहा है।
- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को भाजपा सरकार की नीतियों का मुख्य आधार बताया गया।
- मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि जनता की सेवा करना ही हर जनप्रतिनिधि का सबसे पहला और आखरी दायित्व है।
- चुनाव और वोट की राजनीति पर बात करते हुए उन्होंने साफ किया कि विकास कार्यों का ताल्लुक राजनीतिक नफे-नुकसान से नहीं होता।

वोट की राजनीति पर दिया संदेश

कैलाश विजयवर्गीय ने स्थानीय मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमें चुनाव में वोट दें या न दें, क्षेत्र में विकास के कार्य कभी नहीं रुकेंगे। उन्होंने खुलकर कहा कि यदि जनता वोट देती है तो जनप्रतिनिधि और अधिक उत्साह व ऊर्जा के साथ काम करते हैं, लेकिन यदि किसी वजह से वोट नहीं भी मिलता, तब भी जनता के हक का विकास कार्य बाधित नहीं होगा। इस दौरान मंच से क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया गया और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अधिकार पत्र सौंपे गए।

दो कारें टकराईं, दूल्हा-दुल्हन समेत 7 लोग गाड़ी में फंसे

गेट तोड़कर बाहर निकाला जा सका, एंबुलेंस देरी से आने पर ड्राइवर की मौत

बीना (सागर) (नप्र)। सागर के खुरई में दो कारों की आमने-सामने से टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियां बुरी तरह डैमेज हो गईं। एक कार में दूल्हा-दुल्हन समेत 7 लोग फंस गए। गेट तोड़कर उन्हें बाहर निकाला जा सका। एम्बुलेंस देरी से पहुंचने पर ड्राइवर की मौत हो गई।

हादसा खुरई बायपास स्थित टीहर चौराहा पर सोमवार को हुआ। सभी घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा- खुरई देहात थाना पुलिस के मुताबिक, तोड़ा काछी गांव के रहने वाले प्रहलाद कुशवाहा की शादी बीना के बेसरा गांव की पूजा कुशवाहा से रविवार को हुई थी। रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन की विदाई करा परिवार अर्टिगा कार से वापस लौट रहा था।

इसी दौरान सागर की ओर से आ रही सफारी कार ने सामने चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की और सीधे अर्टिगा से आ टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि अर्टिगा के आगे वाले दोनों गेट दब गए और सवार उसके अंदर फंस गए।

राहगीरों ने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। कड़ी मशक्कत के बाद गेट तोड़कर कार सवारों को बाहर निकाला। सभी को खुरई सिविल अस्पताल पहुंचाया।

सागर नहीं पहुंच पाया घायल ड्राइवर

अर्टिगा के ड्राइवर सुरेंद्र पिता गुलाब सिंह यादव (28) की हालत गंभीर होने पर उसे सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। एम्बुलेंस देरी से आने की वजह से वह समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका। उसने खुरई सिविल अस्पताल में ही दम तोड़ दिया।

गलती से मां की शुगर की दवा खाई, बेटी की मौत

युवती को हो रहा था पेट दर्द, दवा लेने के बाद और बिगड़ी तबीयत

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में दवा का ओवरडोज लेने से युवती की मौत हो गई। युवती को पेट दर्द और बीपी की समस्या थी। परिजनों के अनुसार उसने अपनी दवा के साथ गलती से मां की शुगर की दवा भी खा ली थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक मृतका वंदना मीणा (28) पिता स्वर्गीय महाराज मीणा, गांव बेटा की रहने वाली थी। वह अपने परिवार के साथ रहती थी। वंदना को लंबे समय से बीपी और पेट दर्द की शिकायत रहती थी।

दवा लेने के बाद बिगड़ी तबीयत

रविवार देर रात पेट दर्द होने पर वंदना ने अपनी नियमित दवा ली। इसी दौरान उसने गलती से अपनी मां की शुगर की दवा भी खा ली। कुछ समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे तत्काल एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे।

इलाज के दौरान हुई मौत- अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इलाज के दौरान सोमवार तड़के वंदना की मौत हो गई। घटना की सूचना अस्पताल प्रबंधन ने बैरागढ़ पुलिस को दी।

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा। सोमवार दोपहर पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि दवा लेने में लापरवाही कैसे हुई और मौत का सटीक कारण क्या था।

छह भाई-बहनों में थी शामिल

पुलिस के अनुसार वंदना के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। वह परिवार में छह भाई-बहनों में शामिल थी। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

राम मंदिर चंदा चोरी पर शंकराचार्य ने जताई नाराजगी

बोले- श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ दुर्भाग्यपूर्ण, मंदिरों के लिए अलग संरक्षण व्यवस्था बने

छिंदवाड़ा (नप्र)। छिंदवाड़ा पहुंचे द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। रविवार देर रात उन्होंने कहा कि लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मंदिर जैसी पवित्र जगहों पर भी भ्रष्टाचार हो सकता है। श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, ऐसे धन का सदुपयोग होना चाहिए, न कि आस्था की बलि दी जानी चाहिए।

शंकराचार्य ने कहा कि हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंची है। मंदिरों के ट्रस्ट, अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण

है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहे, तो फिर कौन सी जगह सुरक्षित मानी जाएगी।

उन्होंने देशभर के मंदिरों को सनातन बोर्ड संरक्षण समिति के अधीन लाने की मांग की। उनका कहना था कि सरकारी अधिकारियों को धर्म और नैतिकता की समझ नहीं होती, इसलिए मंदिरों के संचालन और संरक्षण के लिए अलग व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग- धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दे पर भी शंकराचार्य ने सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस देश में जिस समुदाय की संख्या अधिक होती है, शासन भी उसी का प्रभावी होता है।

64 कैनवास से 15,000 किलोमीटर की आध्यात्मिक यात्रा से सिनेमा तक का सफर

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में प्रदर्शित हुई 64 योगिनी पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'बाय 64- व्हिस्पर्स ऑफ द अनसीन'

संस्कृति विभाग एवं काली ट्रस्ट के सहयोग से निर्मित डॉक्यूमेंट्री का अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच प्रदर्शित

भोपाल (नप्र)। 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 मुंबई में कलाकार एवं साधक डॉ. बीना उन्नीकृष्णन की 64 योगिनी प्रदेश के मितावली स्थित मंदिर पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'बाय 64 - व्हिस्पर्स ऑफ द अनसीन' का प्रदर्शन हुआ। संस्कृति विभाग एवं काली ट्रस्ट के सहयोग से निर्मित यह डॉक्यूमेंट्री अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पहली बार प्रदर्शित की गई। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव -दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म समारोह है। यह विशेष रूप से वृत्तचित्र, लघु कथा और एनीमेशन फिल्मों को समर्पित है। इस अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री प्रभात ने डॉ. बीना उन्नीकृष्णन एवं उनकी टीम को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्री दीपक नारायण, एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सुश्री दीप्ति चावला, डॉ. बीना उन्नीकृष्णन, सिनेमैटोग्राफर श्री प्रदीप सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति रही।

हमारी पुरातन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं 64 योगिनी मंदिर: अपर मुख्य सचिव श्री शुक्ला- मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा सामान्य प्रशासन श्री शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि मध्यप्रदेश के मितावली (मुरैना), जबलपुर और खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर हमारी पुरातन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मितावली का 64 योगिनी मंदिर, जिसने भारत की पुरानी संसद भवन की वास्तुकला को प्रेरित किया, यह आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूचि में भी शामिल है।

विरासत और संस्कृति का अद्भुत संगम है फिल्म

64 योगिनि मंदिरों से प्रेरित यह अनूठी फिल्म, संस्कृति, अध्यात्म और विरासत का अद्भुत संगम है। कंकाली ट्रस्ट और मध्यप्रदेश शासन के सहयोग से निर्मित यह डॉक्यूमेंट्री भारत के योगिनी मंदिरों से जुड़ी समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का उत्सव भी है। यह डॉक्यूमेंट्री दर्शकों को ऐसे संसार में ले जाती है, जहाँ कला, आस्था, इतिहास और आत्म-परिवर्तन एक-दूसरे से जुड़कर एक अद्वितीय अनुभव का निर्माण करते हैं।

64 योगिनियों ने मुझे इस कार्य के लिए चुना, यह मेरा सौभाग्य : डॉ. बीना उन्नीकृष्णन

डॉ. बीना उन्नीकृष्णन ने बताया कि लगभग साढ़े बारह वर्ष पूर्व उन्होंने 64 योगिनियों के चित्रांकन की प्रक्रिया को केवल एक दस्तावेज़ के रूप में संजोने की शुरुआत की थी, लेकिन समय के साथ यह प्रयास समर्पण, धैर्य और आत्म-परिवर्तन की प्रेरणादायक सिनेमाई यात्रा बन गया। इस वर्ष उन्होंने 64 मूल चित्रों के साथ भारत के 14 शहरों में लगभग 15,000 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर हजारों लोगों को योगिनी परंपरा से परिचित कराया तथा कला, संस्कृति और अध्यात्म पर व्यापक संवाद स्थापित किया। उन्होंने कहा जब मैंने यह यात्रा शुरू की थी, तब मैं केवल उत्तर खोजती एक कलाकार थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक पुस्तक, प्रदर्शनी, हजारों किलोमीटर की यात्रा और अंततः एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का रूप ले लेगी। योगिनियों ने मुझे भय से परे जाना और अपने स्त्रीत्व तथा अदृश्य मार्ग पर विश्वास करना सिखाया। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने योगिनियों को नहीं चुना, बल्कि योगिनियों ने मुझे चुना है। उन्होंने बताया कि यह डॉक्यूमेंट्री केवल योगिनी मंदिरों के इतिहास और रहस्य को नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आह्वान को पूरा करने के लिए आवश्यक साहस और समर्पण की कहानी भी प्रस्तुत करती है।

संपादकीय

मानसून तुम कब आओगे?

इस बात का डर तो पहले ही से था कि प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने के कारण होने वाले 'अल नीनो' प्रभाव का असर भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा पर भी होगा, लेकिन इसका असर इतनी जल्दी दिखाई देगा, यह नहीं सोचा था। हालांकि देश का मौसम विभाग यह सांत्वना दे रहा है कि जल्द ही मानसून देश भर में सक्रिय होगा, लेकिन उसकी तारीख बढ़ती ही जा रही है। वास्तव में कब आएगा, कोई ठीक-ठीक नहीं बता पा रहा। जो सेटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं, उनमें भी न तो बंगाल की खाड़ी में और न ही अरब सागर में बारिश का कोई बड़ा और मजूबत सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अवर्षा का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस साल कमजोर अल नीनो और कमजोर सोमाली जेट हवाओं के कारण मानसून की चाल धीमी हो गई है। शुरुआती हफ्तों में देश भर में सामान्य से लगभग 40 प्रतिशत तक कम बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी इसके आगे बढ़ने में देरी हो रही है। मौसम विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि प्रशांत महासागर में अल नीनो के प्रभाव से नमी वाली हवाएं कमजोर पड़ रही हैं, जिसके कारण इस साल सामान्य से 90 प्रतिशत तक कम बारिश का अनुमान है। हिंद महासागर में नमी लाने वाले कम दबाव वाली हवाएं, जिन्हें तकनीकी भाषा में सोमाली जेट कहा जाता है, वे भी फिलहाल उतनी मजबूत नहीं हैं। आमतौर पर 1 जून को मानसून केरल पहुंचने के बाद जून मध्य तक देश के बड़े हिस्से में फैल जाता है। लेकिन इस बार वह महाराष्ट्र और बंगाल में ही नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग का दावा है कि मानसून अब जून अंत तथा जुलाई के पहले सप्ताह तक जोर पकड़ेगा। वैसे मानसून का निर्धारित तिथि से देरी से आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर बारिश बहुत कम हुई तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो पहले ही दूसरे वैश्विक संकटों से जूझ रही है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट डरावनी है। इसमे कहा गया है कि देश में मानसून की बारिश के रिकॉर्ड के 126 साल के इतिहास में दूसरा सबसे सूखा जून बीत रहा है। 21 जून तक 57.4 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 42.2 प्रतिशत कम है। इससे पहले 2009 में पूरे जून में कोटे से 49 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी। इससे मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में खेती पर बुरा असर पड़ा था। साथ में यह भी कहा गया है कि मानसून दो हफ्ते बाद अब आगे बढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बना है, जो मानसून को छत्तीसगढ़ तक पहुंचाएगा। रविवार को मेघालय के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। खासी हिल्स जिले के मॉसिनराम में 24 घंटे में 530 मिमी बारिश दर्ज की गई। यानी एक रात में यहां जितनी बारिश हुई, उतनी जोधपुर-बीकानेर में 6 महीने में होती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रविवार को ओले गिरे। वहीं, एमपी के 5 जिलों में आज हीटवेव का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में लू चल सकती है। इस बीच मानसून समय पर न आने के कारण देश में खरीफ की बुवाई 12 जून तक सालाना आधार पर 3.9 प्रतिशत घटकर 84.6 लाख हेक्टेयर रही। बारिश की सारी उम्मीदें अब जुलाई और अगस्त पर टिकी हैं। मानसून की एंट्री 25 जून के बाद हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि सरकार के स्तर पर अभी से कोई ऐहतियाती कदम उठाने और पानी को बचाने के लिए कोई नियम या कार्रवाई नहीं की गई है।

नजरिया

अंशुमान

लेखक संसदी टीवी से सम्बद्ध पत्रकार हैं।

म्यांमार में भारत की नई कूटनीतिक परीक्षा

तख्तापलट के बाद भारत की म्यांमार नीति एक मूल धारणा पर आधारित थी कि नायपीडॉ की केंद्रीय सरकार, चाहे जितनी भी विवादित क्यों न हो, पूरे देश में प्रभावी सत्ता बनी हुई है और इसलिए भारत के प्रमुख हितों के लिए वही सबसे आवश्यक संवाद साझेदार है। लेकिन दिसंबर 2025 के अंत और जनवरी 2026 के बीच हुए चुनावों ने इस धारणा को चुनौती दी। मतदान देश की 330 टाउनशिप में से केवल 265 में ही कराया जा सका। यह आंकड़ा एक ओर सेना की बची हुई प्रशासनिक पहुँच को दर्शाता है, तो दूसरी ओर उस विशाल भूभाग को भी, जिस पर 2021 के बाद से प्रतिरोधी ताकतों का प्रभाव स्थापित हो चुका है।

फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा किए जाने के बाद के लगभग पाँच वर्षों में अपने पूर्वी पड़ोसी के प्रति भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक नीति को एक शब्द में समेटा जा सकता है और वह है निरंतरता। नई दिल्ली ने नायपीडॉ में सैन्य शासन को देश की कार्यकारी सत्ता के रूप में स्वीकार करते हुए उससे हर तरह का संवाद जारी रखा, अपनी संपर्क और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, और सार्वजनिक बयानों को इस तरह संतुलित रखा कि न तो तख्तापलट का समर्थन दिखाई दे और न ही सैन्य नेतृत्व को नाराज़ किया जाए। यह ऐसी नीति थी जिसे एक संक्रमणकालीन दौर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसी रणनीति जो परिस्थितियाँ स्थिर होने तक भारत की स्थिति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बनाई गई थी।

लेकिन परिस्थितियाँ स्थिर नहीं हुईं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बदलती हुई वास्तविकता को सबसे स्पष्ट रूप से न तो किसी सैन्य पराजय, न किसी विद्रोही सफलता और न ही किसी बड़े कूटनीतिक संकट ने उजागर किया; बल्कि एक साधारण-सी प्रतीत होने वाली राजकीय यात्रा ने इसे सबसे अधिक स्पष्ट किया। मई-जून 2026 में म्यांमार के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग का नई दिल्ली आगमन केवल एक नियमित राजकीय यात्रा नहीं था। सत्ता ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा और 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत के उपरांत जारी संयुक्त वक्तव्य ने संकेत दिया कि भारत-म्यांमार संबंध एक ऐसे मोड़ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पुराने आकलनों की सीमाएँ स्पष्ट होने लगी हैं। इस यात्रा का वास्तविक महत्व किसी नई नीति-घोषणा या कूटनीतिक उपलब्धि में नहीं, बल्कि इस तथ्य में निहित था कि इसने उन जमीनी परिवर्तनों को उजागर कर दिया जिन्हें नई दिल्ली अब अधिक समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकती।

हकीकत में पिछले पाँच वर्षों से भारत जिस नीतिगत ढाँचे के आधार पर म्यांमार के साथ अपने संबंधों को निभा रहा था, वह इस धारणा पर टिका था कि नायपीडॉ की केंद्रीय सत्ता अंततः पूरे देश पर अपना प्रभाव बनाकर रखेगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा, आज की स्थिति यह है कि म्यांमार का राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पहले से कहीं अधिक बिखर चुका है। ऐसे में पुराना नीति-ढाँचा उस वास्तविकता को समझने और संभालने के लिए पर्याप्त नहीं रह गया है, जिसके लिए उसे मूल रूप से तैयार किया गया था। राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग की यह यात्रा वस्तुतः उसी बदलती वास्तविकता की औपचारिक और प्रतीकात्मक मान्यता थी, जिसने भारत-म्यांमार संबंधों तथा व्यापक क्षेत्रीय समीकरणों को एक नए दौर में प्रवेश करा दिया है।

यहाँ यह समझना बेहद ज़रूरी है कि भारत के लिए म्यांमार सिर्फ़ एक पड़ोसी देश नहीं है। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रवेश द्वार है, जो पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है। साथ ही, बंगाल की खाड़ी में भारत की सामरिक उपस्थिति को मज़बूत करने और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने में भी म्यांमार की अहम भूमिका है। यही वजह है कि वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों का सीधा असर भारत की सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर की स्थिरता और व्यापक क्षेत्रीय रणनीति पर पड़ता है। इसलिए नई दिल्ली ने हमेशा म्यांमार के मसले पर आदर्शवादी दृष्टिकोण के बजाय अपने व्यावहारिक राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है।

तख्तापलट के बाद भारत की म्यांमार नीति एक मूल धारणा पर आधारित थी कि नायपीडॉ की केंद्रीय सरकार, चाहे जितनी भी विवादित क्यों न हो, पूरे देश में प्रभावी सत्ता बनी हुई है और इसलिए भारत के प्रमुख हितों के लिए वही सबसे आवश्यक संवाद साझेदार है। लेकिन दिसंबर 2025 के अंत और जनवरी 2026 के बीच हुए चुनावों ने इस धारणा को चुनौती दी। मतदान देश की 330 टाउनशिप में से केवल 265 में ही कराया जा सका। यह आंकड़ा एक ओर सेना की बची हुई प्रशासनिक पहुँच को दर्शाता है, तो दूसरी ओर उस विशाल भूभाग को भी, जिस पर 2021 के बाद से प्रतिरोधी ताकतों का प्रभाव स्थापित हो चुका है।

कूटनीतिक तौर पर देखा जाए तो यह भारत की विदेश नीति के लिए कोई हाशिये का प्रश्न नहीं है, बल्कि एक केंद्रीय चुनौती है। नई दिल्ली की म्यांमार नीति तीन परस्पर जुड़ी प्राथमिकताओं से संचालित रही है, सीमा की स्थिरता, संपर्क अवसंरचना का विकास, और चीन की रणनीतिक पैठ को सीमित करना। इन्हीं कारणों से भारत ने लोकतांत्रिक दुनिया द्वारा अलग-थलग किए जाने के बावजूद ततमाडॉ यानी म्यांमार सेना को अपना मुख्य साझेदार बनाए रखा। लेकिन यह रणनीतिक गणित अब पहले जैसा काम नहीं कर रहा है। आज वे जातीय सशस्त्र संगठन (EAOs) उन इलाकों पर नियंत्रण रखते हैं जिनसे होकर भारत की अधिकांश कनेक्टिविटी परियोजनाएँ गुजरती हैं। ऐसे में केवल नायपीडॉ पर केंद्रित संपर्क भारत के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं रह गया है।

दरअसल, कूटनीतिक स्तर पर भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि उसे म्यांमार की सरकार से संबंध रखने चाहिए या नहीं। असली चुनौती यह है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप वह अपने संपर्कों और संवाद का दायरा कितना व्यापक बनाता है। विदेश नीति में अक्सर यह कहा जाता है कि देशों के संबंध राज्यों से होते हैं, लेकिन म्यांमार की मौजूदा स्थिति इस सिद्धांत की सीमाओं को भी उजागर करती है। आज देश के कई हिस्सों में वास्तविक प्रभाव और नियंत्रण केवल केंद्रीय सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न जातीय सशस्त्र संगठनों और स्थानीय शक्तियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में केवल आधिकारिक सरकारी तंत्र पर निर्भर रहना भारत के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जिन समूहों का सीमावर्ती क्षेत्रों, व्यापार मार्गों और स्थानीय सुरक्षा स्थितियों पर प्रभाव है, उनकी उपेक्षा करने का अर्थ होगा ज़मीन पर मौजूद वास्तविकताओं को नज़रअंदाज़ करना। भारत के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण यही होगा कि वह अपनी पारंपरिक सरकारी संपर्क व्यवस्था को बनाए रखते हुए उन सभी प्रभावशाली पक्षों के साथ संवाद के रास्ते भी खुले रखे, जो म्यांमार के भविष्य और भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

1 जून को जारी भारत-म्यांमार संयुक्त बयान ने इस अंतर्विरोध को स्वीकार तो किया, लेकिन उसका समाधान प्रस्तुत नहीं किया। भारत-म्यांमार सीमा पर सत्ता का बिखरता ढाँचा इस बात को स्पष्ट करती हैं कि केवल नायपीडॉ के साथ संवाद अब पर्याप्त नहीं रह गया है। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो भारत की म्यांमार से लगने वाली सीमा अब किसी एक राज्य के साथ साझा की गई सीमा नहीं रह गई है। यह अनेक शक्ति केंद्रों में विभाजित एक सीमांत क्षेत्र बन चुकी है।

भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी इसी संदर्भ में समझना होगा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर विद्रोही गतिविधियाँ, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध आवाजाही और शरणार्थी प्रवाह जैसी चुनौतियाँ सीधे म्यांमार की स्थिति से जुड़ी हुई हैं। इसलिए भारत के लिए म्यांमार केवल विदेश नीति का विषय नहीं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा का भी प्रश्न है। हालाँकि इस बदलती वास्तविकता के सामने भारत पूरी तरह स्थिर भी नहीं रहा है। नायपीडॉ के साथ औपचारिक संबंधों की निरंतरता के पीछे एक अधिक परतदार और सोच-समझकर तैयार की गई रणनीति धीरे-धीरे आकार ले रही है।

भारत को म्यांमार को केवल संकट के चश्मे से देखने के बजाय एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखना होगा। पूर्वोत्तर भारत के विकास, आसियान तक पहुँच, बंगाल की खाड़ी में समुद्री प्रभाव और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की दृष्टि से म्यांमार की भूमिका आने वाले वर्षों में और भी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए भारत की नीति का लक्ष्य केवल वर्तमान संकट का प्रबंधन नहीं, बल्कि भविष्य की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप एक दीर्घकालिक रणनीतिक ढाँचा तैयार करना होना चाहिए।

इस दृष्टि से राष्ट्रपति की यात्रा आवश्यक कूटनीतिक औपचारिकता थी। लेकिन उससे कहीं अधिक कठिन और महत्वपूर्ण कार्य अभी बाकी है, नायपीडॉ से परे संबंधों का निर्माण, सीमा सुरक्षा और सीमा-पार संपर्क के बीच संतुलन स्थापित करना, तथा म्यांमार के विविध शक्ति केंद्रों को ध्यान में रखते हुए एक अधिक व्यावहारिक, लचीली और भारत-केंद्रित नीति विकसित करना। पूर्व की ओर देखते हुए नई दिल्ली के सामने यही वास्तविक रणनीतिक चुनौती है।

इलेक्ट्रिक वाहन- भारत के लिए अवसर या चुनौती?

ऊर्जा प्रबंधन

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

दुनिया के ऑटोमोबाइल बाजार में बड़ा बदलाव धीमे-धीमे आकार ले रहा है। पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाली पारंपरिक गाड़ियाँ, जो पिछले सौ वर्षों से आधुनिक परिवहन व्यवस्था की पहचान रही हैं, अब धीरे-धीरे अपनी पकड़ खो रही हैं। उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन ले रहे हैं। हाल में प्रकाशित एक अध्ययन ने यह दावा किया है कि यूरोप और चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अब निर्णायक मोड़ पर पहुँच चुकी है, बाजार स्वयं इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में आगे बढ़ रहा है और पारंपरिक ईंधन आधारित वाहनों की वापसी मुश्किल होती जा रही है। यह केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और वैश्विक राजनीति तक असर डालने वाला बदलाव है। सवाल यह है कि इस वैश्विक परिवर्तन के बीच भारत कहाँ खड़ा है?

यूरोप और चीन के संदर्भ में किए गए अध्ययन का सार है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से कई गुना बढ़ रही है, यानी हर कुछ वर्षों में इनकी संख्या लगभग दोगुनी हो रही है और इन देशों में यह बाजार अब अपने बल पर आगे बढ़ने लगा है। शोधकर्ताओं के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री, पेट्रोल-डीज़ल कारों की घटती मांग, बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते विकल्प और कीमतों में कम होता अंतर इस बात के संकेत हैं कि अब बाजार तेजी से बदलाव की दिशा में बढ़ चुका है, जहाँ से पुराने ढर्रे पर लौटना आसान नहीं होगा। चीन और यूरोप में यह परिवर्तन केवल बाजार की ताकत से नहीं आया, बल्कि वर्षों की नीति, सब्सिडी, सरकारी निवेश और उद्योग की तैयारी ने मिलकर इसे संभव बनाया है।

आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और तेजी से शहरीकरण, बढ़ती आय, ऊर्जा आयात और प्रदूषण जैसी चुनौतियों के बीच परिवहन का भविष्य तय करने की स्थिति में है। भारत की सड़कों पर आज भी पेट्रोल और डीज़ल वाहन हावी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की उपस्थिति अब केवल प्रयोगात्मक नहीं रही। दोपहिया और तिपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक बसें भी धीरे-धीरे जगह बना रही हैं। लेकिन चारपहिया निजी वाहनों के मामले में भारत अभी शुरुआती चरण में है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत भी उसी 'निर्णायक मोड़' की ओर बढ़ रहा है, जिसकी चर्चा यूरोप और चीन के संदर्भ में हो रही है? भारत के सामने इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में बढ़ने का सबसे बड़ा तर्क आर्थिक है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में आयात करता है। तेल की कीमतों में वैश्विक उतार-चढ़ाव सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। पेट्रोल-डीज़ल की कीमत बढ़ने पर महँगाई बढ़ती है, परिवहन लागत बढ़ती है और विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ता है। ऐसे में अगर परिवहन का बड़ा हिस्सा बिजली आधारित हो जाए, तो तेल आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है। अध्ययन भी बताता है कि तेल आयात करने वाले देशों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर संक्रमण से आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और व्यापार संतुलन बेहतर हो सकता है।

पर्यावरणीय नजरिये से भी भारत के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बदलाव केवल विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बनता जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। परिवहन क्षेत्र इसका बड़ा कारण है। पेट्रोल और डीज़ल वाहनों से निकलने वाला धुआँ कार्बन उत्सर्जन के साथ-साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्म कणों के रूप में स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धताएँ जताई हैं। ऐसे में अगर परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार होता है, तो कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि यह भी सच है कि इलेक्ट्रिक वाहन तभी वास्तव में हरित विकल्प होंगे, जब बिजली उत्पादन में भी स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़े। लेकिन भारत की चुनौतियाँ यूरोप और चीन से अलग हैं। चीन ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बड़े पैमाने पर सरकारी सब्सिडी, बैटरी उत्पादन, सार्वजनिक खरीद और विनिर्माण क्षमता के सहारे विकसित किया। यूरोप ने भी कठोर उत्सर्जन नियमों और प्रोत्साहनों के जरिए बाजार को दिशा दी। भारत में नीति-स्तर पर फेम जैसी योजनाएँ और राज्य सरकारों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियाँ आई हैं, लेकिन अभी भी बुनियादी ढाँचे की कमी बड़ी बाधा है। चार्जिंग स्टेशन सीमित हैं, बैटरियों की लागत अधिक है और उपभोक्ताओं के मन में अब भी यह आशंका बनी हुई है कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बैटरी खत्म होने पर चार्जिंग सुविधा समय पर मिलेगी या नहीं। ग्रामीण और छोटे शहरों में यह चुनौती और अधिक जटिल है। इसलिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन परिवर्तन केवल बाजार के भरोसे नहीं हो सकता, इसके लिए नीति और निवेश दोनों की निरंतर जरूरत होगी।अध्ययन में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता केवल सब्सिडी से नहीं आती, बल्कि सब्सिडी, अनिवार्य नीतियाँ, सार्वजनिक खरीद और बाजार उपलब्धता के संयुक्त प्रभाव से इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता अपने आप तेज़ी से बढ़ने लगती है। यह बात भारत के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। अगर केवल उपभोक्ताओं से अपेक्षा की जाए कि वे महँगे इलेक्ट्रिक वाहन खरीद लें, तो बदलाव धीमा रहेगा। लेकिन अगर सरकार सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी सेवाओं, डिलीवरी नेटवर्क और सरकारी वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य रूप से बढ़ाए, तो मांग और बाजार दोनों तेजी से बदल सकते हैं। भारत में दोपहिया और तिपहिया क्षेत्र में यही शुरुआती संकेत दिखाई भी दे रहे हैं।

यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या भारत इलेक्ट्रिक वाहन केवल आयातित तकनीक का बाजार बनेगा या इस परिवर्तन को औद्योगिक अवसर में बदल पाएगा? बैटरी निर्माण, लिथियम आपूर्ति, सेमीकंडक्टर, चार्जिंग तकनीक और स्थानीय विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत के पास असीमित अवसर है। अगर भारत ने समय रहते उत्पादन क्षमता विकसित की, तो वह न केवल घरेलू मांग पूरी कर सकता है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा भी बन सकता है। लेकिन अगर नीति में स्पष्टता और निवेश में निरंतरता नहीं रही, तो भारत केवल उपभोक्ता बाजार बनकर रह जाएगा।यह भी गौरतलब है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का परिवर्तन केवल तकनीकी बदलाव नहीं, सामाजिक बदलाव भी है। लाखों लोग ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, ईंधन आपूर्ति, इंजन पार्ट्स और पारंपरिक वाहन उद्योग से जुड़े हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में इंजन की जटिलता कम होती है, रखरखाव की प्रकृति बदलती है और रोजगार का ढाँचा भी बदल सकता है। इसलिए यह संक्रमण केवल पर्यावरण नीति नहीं, रोजगार और कौशल विकास की नीति भी है। भारत को इस बदलाव के लिए कार्यबल को तैयार करना होगा। अध्ययन के अनुसार अगर दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार इसी गति से जारी रहा, तो 2030 के आसपास तेल की मांग अपने चरम पर पहुँच सकती है। भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए यह अवसर हो सकता है, लेकिन तेल निर्यातक देशों की वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार में इससे अस्थिरता भी पैदा हो सकती है। इसलिए भारत को ऊर्जा सुरक्षा की नई रणनीति बनानी होगी। असल प्रश्न यह है कि भारत इस बदलाव में क?या अग्रणी बनेगा। दुनिया के बड़े बाजारों ने संकेत दे दिए हैं कि भविष्य इलेक्ट्रिक परिवहन की दिशा में बढ़ रहा है। भारत के पास भी अवसर है कि वह इसे केवल पर्यावरणीय मजबूरी के रूप में न देखे, बल्कि आर्थिक, औद्योगिक और ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति के रूप में अपनाएं।

राम मंदिर में चोरी, सामूहिक लूट है

आस्था से खिलवाड़

डॉ. हरीशकुमार सिंह

अपने देश में हजारों की संख्या में प्रसिद्ध मंदिर हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक हैं और भक्तजन मंदिरों में दान देकर, नगद या सोने-चांदी की कोई वस्तु चढ़ाना पुण्य का काम मानते हैं। छोटे मंदिरों में यह दान पुण्य की राशि से ही मंदिर का रखरखाव और पुजारी का जीवनयापन चलता है। कई प्रसिद्ध मंदिरों की देखभाल के लिए ट्रस्ट बन गये हैं तो कई मंदिर शासन के अधीन हैं और प्रशासक की नियुक्ति सरकार करती है। मंदिरों में चोरी का इतिहास काफी पुराना है और ज्यादातर मामलों में चोरों का निशाना अष्टधातु, पीतल, सोने- चांदी की प्राचीन मूर्तियाँ और गहने होते हैं। मंदिरों से करोड़ों की मूर्तियों की चोरी कोई नई बात नहीं है। मंदिर के कर्मचारियों द्वारा चढ़ावे की चोरी भी होती आई है और वर्ष 2023 में तिरुपति बालाजी मंदिर के कर्मचारी रवि कुमार को पकड़ा गया था जिसने पिछले बीस वर्षों में सौ करोड़ रुपये से अधिक की नगदी चोरी की थी। वर्ष 2024 में ही तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद की जांच में लड्डुओं के इस्तेमाल में लाया जाने वाला घी मिलावटी पाया गया था और उसमें जानवरों की चर्बी पाई गई। विश्व प्रसिद्द उज्जैन के श्री महाकालेश्वर के दर्शनों को लेकर भी दिसम्बर 2024 में एक बड़ा घोटाला तत्कालीन कलेक्टर ने पकड़ा था जिसमें पण्डे - पुजारी नहीं बल्कि मंदिर समिति से जुड़े कर्मचारी , निजी एजेंसी के गार्ड , कुछ मीडियाकर्मी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से अवैध तरीके से हजारों रुपये लेकर उन्हें वीवीआईपी व्यवस्था के तहत आसानी से दर्शन कराकर, खुद करोडपति बन बैठे। पता नहीं यह सिलसिला कब से चला आ रहा था और करोड़ों की कमाई ये कर्मचारी कर चुके थे। आज भी अवैध कमाई का यह सिलसिला रुका नहीं है। जाहिर है मंदिरों से चोरी, दर्शन के नाम पर अवैध वसूली, मंदिर प्रसाद में घोटाले उतने ही पुराने हैं जितने मंदिर। पर अयोध्या के राम मंदिर में चोरी किसी एक या दो कर्मचारी ने नहीं की है और न ही इसे मंदिर की प्रबंध समिति ने पकड़ा है। मंदिर के छोटे कर्मचारियों ने जब करोड़ों की जमीन और अन्य संपत्ति खडी कर ली तो ये निगाह में आने लगे और इनमें से ही कोई असली रामभक्त ने सामने आकर मामला उजागर किया। केवल मंदिर से चढ़ावे की रकम ही नहीं लूटी गई है बल्कि सोने चांदी की वस्तुएं जो भक्तों ने बड़े आस्था और विश्वास से भगवान के चरणों में समर्पित की गायब हैं। यह सामूहिक डकैती का विलक्षण उदहारण है जिसे एक संगठित गिरोह ने अंजाम दिया है। ख़ुशी की बात यह है कि यह लूट पकड़ी गई है क्योंकि भगवान भी यह देख कर दुखी हो रहे थे और उन्होंने ही इन डकैतों को पकडवाने में अपने दूत शिकायतकर्ताओं के रूप में भेजे।

आम आदमी पार्टी ने जून 2021 में अभी जिन पर दान की राशि के गबन के आरोप हैं उनमें से चम्पत राय,अनिल मिश्रा पर मंदिर के लिये जमीन खरीदी में भी करोड़ों रुपये की हेराफेरी के आरोप लगाये थे और तब जमीन आज के बाजार भाव से खरीदी गई है कहकर ये बच निकले थे क्योंकि तब कोई जांच बैठाने को तैयार नहीं था। मंदिर बनने के दौरान भी भारी कमीशनखोरी की गई है और ये बातें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं।

सदियों के इंतज़ार, मारकाट,आंदोलनों और हजारों आहुतियों के बाद अंततः भारतवर्ष में वह सुखद मंगल क्षण 22 जनवरी 2023 को आया था जब अयोध्या में श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की थी और हर सनातनी उन पर गर्व और अभिमान कर रहा था। पूरे देश में इस दिन दिए जलाकर महोत्सव मनाया गया था। पर अयोध्या में देश के हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े राम मंदिर में दान और चढ़ावे की राशि में गबन,हेराफेरी, चोरी से हर भक्त आहत है और मंदिर के वर्तमान कर्ताधर्ताओं ने केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा भी एक झटके में धूमिल कर दी है। जिस विश्वास के साथ नए राम मंदिर की जिम्मेदारी इन लोगों को सौंपी गई थी इन्होनें भक्तों की आस्था के साथ भी धोखाधड़ी की है। समय की मांग है कि इन अधर्मियों के घरों पर बुलडोजर चले या न चले इन पर ही बुलडोजर चलना चाहिए।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

सेवा, सिफारिश और स्थानांतरण का सीजन

व्यंग्य

विनोद कुमार विक्की

लेखक व्यंग्यकार हैं।

जून महीने में सरकारी कार्यालयों में सूरज की गर्मी और स्थानांतरण की सरगर्मी से तापमान चालीस डिग्री तथा सरकारी कर्मचारियों का रक्तचाप एक सौ बीस बटा अस्सी के पार पहुँच जाता है।

जून का पहला सप्ताह आते ही सरकारी विभागों का मुख्यालय ब्रह्मांड बन जाता है। कर्मचारी मंगल ग्रह स्वरूप मंत्रीजी और बृहस्पति स्वरूप विभागीय बाबू के बीच क्षुद्रग्रह बनकर चक्कर काटने लगते हैं।

जून के मानसूनी मौसम में बिना बादल, बिजली और निम्न दाब के ही कर्मचारियों के दिलों में भय का चक्रवात उमड़ने लगता है। फलस्वरूप मौद्रिक मानसून की बूंदाबांदी से स्थापना कार्यालय और मंत्रालय संयुक्त रूप से भीगने लगता है।

व्हाट्सऐप पर विभिन्न विभागों से निर्गत ट्रांसफर सूचियाँ वायरल होने लगती हैं और कर्मचारी उन्हें उसी श्रद्धा से पढ़ते तथा अग्रसारित करते हैं, जैसे विद्यार्थी परीक्षा परिणाम को।

सरकारी कर्मचारी कहीं का स्थायी निवासी नहीं होता, वह केवल अगले ट्रांसफर तक का अस्थायी किरायेदार होता है। तीन वर्ष पहले जिस जिले में उसने बड़े जतन से अपना तंबू गाड़ा था, स्थानीय परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाया था, किराए का मकान खोजा था, बच्चों के स्कूल, ट्यूशन, दूधवाले, पानवाले से लेकर सब्जीवाले तक से आत्मीय संबंध स्थापित कर लिए थे और कार्यालय में अधीनस्थों तथा सहकर्मियों से तालमेल बिठा पाया था, तभी अचानक शासन को याद आ जाता है कि 'प्रशासनिक दृष्टिकोण' से उसका किसी अन्य जिले में होना अधिक आवश्यक है।

मनचाहा पदस्थापन पाने की चाह रखने वाले कुछ महानुभाव शीतनिद्रा से जागे साँप की तरह अचानक सक्रिय हो जाते हैं। वे मुख्यालय के बाबू से लेकर माननीय के दरबार तक कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, मानो ट्रांसफर पंचमी के दौरान सरकारी आदेश रूपी नागमणि प्राप्त करके ही कार्यस्थल पर लौटेंगे। किसी के हाथ में आवेदन होता है, किसी के हाथ में सिफारिश, तो किसी के हाथ में मोटी फाइल, जिसमें सेवा पुस्तिका से अधिक 'सेवा शुल्क' भरा होता है।

उधर बाबू वर्ग का कक्ष भी किसी धार्मिक स्थल का रूप ले लेता है। दर्शनार्थियों का जमावड़ा लग जाता है। पिता अथवा पत्नी की बीमारी, पति-पत्नी की एक स्थान पर नौकरी तथा अन्य पारिवारिक समस्याओं के आधार पर स्थानांतरण की अर्जियों के अतिरिक्त भार से बाबू की लॉगबुक कराहने लगती है। आगंतुक मुस्कुराकर नमस्ते करते हैं और चाय-पानी का आग्रह करते हैं।

बाबू भी सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए ज्ञान देते हैं– 'अजी, आप मेरे स्तर से बिल्कुल निश्चिंत रहें, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है।'

'ऊपर वाला' कौन है? इसका अर्थ और आकलन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है।

ट्रांसफर सूची जारी होते ही कार्यालयों में 'हम साथ-साथ हैं' वाला भावनात्मक दृश्य उभरने लगता है। जो सहकर्मी कल तक एक-दूसरे की फाइल रोकने, टांग खींचने अथवा वरीय पदाधिकारी से चुगली करने में व्यस्त थे, वे भी गले मिलकर भाई चारा प्रकट करते हैं।

जिनका ट्रांसफर नहीं होता, वह अगले दिन कार्यालय में ऐसे प्रवेश करता है, जैसे युद्ध जीतकर लौटा कोई विजेता सेनापति। चेहरे पर विजय मुस्कान, चाल में आत्मविश्वास और बातों में रहस्य का पुट। पूछने पर बस इतना कहता है–'ऊपर तक बात पहुँच गई थी।'

बहरहाल, आम आदमी को जून माह की चिलचिलाती धूप, लू और नौतपा का भय सताता है, वहीं ट्रांसफर रूपी टाइफून से सरकारी सेवकों में भय और बदहवासी का माहौल बना रहता है।

बारिश नहीं, हमारी तैयारियों की परीक्षा है मानसून

हर वर्ष मानसून आने से पहले नगर निकाय और प्रशासन नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष प्रबंध करने के दावे करते हैं। लेकिन पहली ही तेज बारिश इन दावों की वास्तविकता सामने ले आती है। सड़कें पानी में डूब जाती हैं, यातायात बाधित हो जाता है, कई स्थानों पर बिजली व्यवस्था चरमरा जाती है और लोगों का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। यदि यही स्थिति हर वर्ष दोहराई जा रही है, तो यह प्राकृतिक आपदा से अधिक हमारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की कमजोरी को दर्शाती है। मानसून की चुनौती केवल शहरों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अत्यधिक या अनियमित वर्षा किसानों की चिंता बढ़ा देती है। कहीं खेत जलमग्न हो जाते हैं तो कहीं समय पर वर्षा न होने से फसल प्रभावित होती है। कच्चे मकानों को नुकसान, ग्रामीण सड़कों का टूटना और सीमित संसाधनों के कारण गाँवों में जीवन और कठिन हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अलग-अलग रणनीति बनाई जाए।

सामयिक

संध्या अग्रवाल

लेखक साहित्यकार हैं।

तपती गर्मी के लंबे दौर के बाद जब आसमान में काले बादल उमड़ते हैं और धरती पर बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं, तो वातावरण में एक अलग ही ताजगी घुल जाती है। मिट्टी की सोंधी महक, पेड़ों की धुली हरियाली और बच्चों की खिलखिलाहट मानसून के आगमन का सुखद संदेश देती है। भारतीय जनजीवन में वर्षा केवल एक ऋतु नहीं, बल्कि जीवन, कृषि और समृद्धि का आधार है। किंतु विडंबना यह है कि जिस मानसून का बेसब्री से इंतजार किया जाता है, वही कुछ घंटों की बारिश के बाद चिंता और अव्यवस्था का कारण बन जाता है। ऐसे में प्रश्न यह नहीं कि मानसून कितना प्रबल है, बल्कि यह है कि क्या हमारी तैयारियाँ उसके अनुरूप हैं?

हर वर्ष मानसून आने से पहले नगर निकाय और प्रशासन नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष प्रबंध करने के दावे करते हैं। लेकिन पहली ही तेज बारिश इन दावों की वास्तविकता सामने ले आती है। सड़कें पानी में डूब जाती हैं, यातायात बाधित हो जाता है, कई स्थानों पर बिजली व्यवस्था चरमरा जाती है और लोगों का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। यदि यही स्थिति हर वर्ष दोहराई जा रही है, तो यह प्राकृतिक आपदा से अधिक हमारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की कमजोरी को दर्शाती है।

मानसून की चुनौती केवल शहरों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अत्यधिक या अनियमित वर्षा किसानों की चिंता बढ़ा देती है। कहीं खेत जलमग्न हो जाते हैं तो कहीं समय पर वर्षा न होने से फसल प्रभावित होती है। कच्चे मकानों को नुकसान, ग्रामीण सड़कों का टूटना और सीमित संसाधनों के कारण गाँवों में जीवन और कठिन हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अलग-अलग रणनीति बनाई जाए।

आज जलवायु परिवर्तन ने मानसून के स्वरूप को भी बदल दिया है। कभी लंबे समय तक वर्षा नहीं होती और कभी कुछ घंटों में ही रिकॉर्ड बारिश हो जाती है। मौसम की यह अनिश्चितता स्पष्ट संकेत देती है कि अब पुरानी व्यवस्थाओं के भरोसे नहीं रहा जा सकता। आधुनिक जल निकासी प्रणाली, सटीक मौसम पूर्वानुमान, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और समयबद्ध तैयारी आज की अनिवार्य आवश्यकता है। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप विकास योजनाओं में भी आवश्यक परिवर्तन करना होगा।

हाल के वर्षों में यह दृश्य लगभग हर मानसून में देखने को मिलता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली या आईटी हब बेंगलुरु—कुछ घंटों की तेज बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। कई स्थानों पर वाहन बंद पड़ जाते हैं, यातायात घंटों तक प्रभावित रहता है और लोगों को अपने दैनिक कार्यों के लिए भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति बताती है कि समस्या केवल अधिक वर्षा की नहीं, बल्कि शहरों की जल निकासी व्यवस्था, अतिक्रमण और दूरदर्शी शहरी नियोजन की भी है।

सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि बरसात के दिनों में जिन शहरों में पानी सड़कों पर बहता दिखाई देता है, वहीं कुछ महीनों बाद वही शहर पेयजल संकट से जूझने लगते हैं। इसका प्रमुख कारण वर्षा जल का समुचित संरक्षण न होना है। यदि वर्षा जल संचयन को व्यापक स्तर पर अपनाया जाए, पुराने तालाबों और जलाशयों का संरक्षण किया जाए तथा भूजल पुनर्भरण की दिशा में गंभीर प्रयास हों, तो बारिश की हर बूंद भविष्य के लिए अमूल्य संपदा बन सकती है। पानी को केवल बह जाने देना दूरदर्शिता नहीं, बल्कि आने वाले संकट को आमंत्रित करना है।

आज आवश्यकता केवल वर्षा जल संचयन की बात करने की नहीं, बल्कि उसे प्रभावी रूप से लागू करने की भी है। प्रत्येक नए भवन, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय और औद्योगिक परिसर में वैज्ञानिक ढंग से तैयार किए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को फ़िल्टर कर भूमिगत रिचार्ज पिट अथवा संग्रहण टैंकों तक पहुँचाने की व्यवस्था न केवल भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि शहरी जलभराव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि स्थानीय निकाय समय-समय पर इन प्रणालियों का निरीक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करें, तो वर्षा की प्रत्येक बूंद भविष्य के लिए अमूल्य जल-संपदा में बदल सकती है।

वर्षा जल संचयन को केवल सरकारी नियम तक सीमित रखने के बजाय जनभागीदारी का अभियान बनाना होगा। जिस प्रकार आज नए मकानों की छतों पर सौर ऊर्जा के पैनल तेजी से सामान्य होते जा रहे हैं और लोग उन्हें भविष्य की आवश्यकता मानकर अपना रहे हैं, उसी प्रकार वर्षा जल संचयन की व्यवस्था भी प्रत्येक नए भवन का अनिवार्य हिस्सा बननी चाहिए। घर की छत पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से सीधे भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था से जोड़ दिया जाए, तो हर वर्ष लाखों लीटर पानी धरती के भीतर पहुँच सकता है। इससे एक ओर जलभराव की समस्या कम होगी, वहीं दूसरी ओर भूजल स्तर को भी नया जीवन मिलेगा। यह केवल पर्यावरण संरक्षण का उपाय नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है।

इस पूरी व्यवस्था में नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नालियों में प्लास्टिक और कचरा फेंकना, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता की अनदेखी करना तथा पर्यावरण के प्रति उदासीन रहना अनेक समस्याओं को जन्म देता है। केवल प्रशासन को दोष देने से समाधान नहीं निकलेगा। स्वच्छता, जल संरक्षण और सार्वजनिक संपत्तियों के प्रति जिम्मेदारी का भाव प्रत्येक नागरिक में विकसित होना चाहिए। जब समाज और प्रशासन मिलकर कार्य करते हैं, तभी स्थायी परिवर्तन संभव होता है।

आवश्यकता इस बात की है कि मानसून को हर वर्ष आने वाली समस्या के रूप में नहीं, बल्कि बेहतर प्रबंधन की परीक्षा के रूप में देखा जाए। पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक योजना, जल संरक्षण, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और प्रशासन तथा नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय से ही वर्षा को संकट नहीं, बल्कि समृद्धि का माध्यम बनाया जा सकता है। समय रहते उठाए गए छोटे-छोटे कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं को टाल सकते हैं।

मानसून हर वर्ष हमारी चौखट पर दस्तक देता है। वह अपने साथ जीवनदायिनी बूंदें लेकर आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका स्वागत दूरदर्शिता से करें या फिर हर बार अव्यवस्था का दोष बारिश पर मढ़ते रहें। प्रकृति अपना दायित्व पूरी निष्ठा से निभाती है, अब हमारी बारी है। यदि हम हर मानसून के बाद कारण तलाशने के बजाय हर मानसून से पहले समाधान सुनिश्चित करने की आदत विकसित कर लें, तो बारिश अव्यवस्था का नहीं, खुशहाली और समृद्धि का संदेश लेकर आएगी। सच तो यही है कि बारिश नहीं, हमारी तैयारियों की परीक्षा है मानसून।

लेखन और छपास-दुनिया रखती है ठेंगे पर

विचार

मोहन वर्मा

लेखक पत्रकार हैं।

कहते हैं समय परिवर्तनशील है। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। मगर हाँ, जो सौ टंच और होगा खरा-वही रहेगा हरा। बात लेखन की करें, साहित्य की करें तो अग्रज रचनाकारों की कालजयी रचनाएं समय की कसौटी पर कल भी खरी थी, आज भी खरी है और कल भी राह दिखाती रहेंगी। परिवर्तनशील समय की कसौटी पर आज के लेखन की बात करें तो वो समय से पहले बूढ़े नज़र आते नौजवानों की तरह दिखाई देता है ।

बात दरअसल बीते पाँच दशकों के अपने ही लिखे पर एक निगाह डालते हुए आत्म साक्षात्कार से निकलकर बाहर आई जब अख़बारों के 'पत्र सम्पादक के नाम' कालम में किसी समस्या को लेकर लिखी छोटी सी चिट्ठी भी छप जाती थी तो लोग न सिर्फ पढ़ते थे बल्कि रोककर हौंसला अफजाई करते थे। अपने समय में लेख कहानी कविताएं पढ़कर पाठक रोमांचित होता था। पत्र पत्रिकाओं का इन्तजार बना रहता था। आज समय बदल गया है ।

लेखन की दुनिया के जिन सूरमाओं को और सोशल मीडिया पर ज्ञान पेलते बुद्धिजीवीओं को अपने लिखे पर खुद से ज्यादा भरोसा हो उन्हें आज के दिग्गज रचनाकारों की रचनाओं, उनकी सोशल मीडिया पर आये दिन आती पोस्ट और कहानी कविताओं पर उनकी प्रशंसा में आते लाईक कमेंट्स पर एक निगाह जरूर डाल लेना चाहिये (हालांकि वे सौ टका निगाह डालते ही होंगे) कि हालत क्या है? अरे जब दिग्गज लेखक अपने लिखे पर आते चार छह लाईक और एक दो कमेंट्स देखकर पानी पानी हुए हो रहें हो तो आप किस खेत की मूली हैं?

रील,वॉटसप,फ़ेसबुक पर अपना लिखा,छपा डालने वाले खूब जानते है कि उनकी पोस्ट पर लाईक कमेंट्स के कैसे लाले पड रहे है। लोग उन्हें देखकर ठीक वैसे ही अनदेखा करते है जैसे व्यक्तिगत हमें आपको देख कर अनदेखा करते है। अगर आपने फेसबुक पर दायीं और बना आँख का निशान देखा हो तो वो बताता है इस पोस्ट को कितनों ने देखा है द्य ये संख्या हजारों में होती है । छह आठ लाईक और एक दो कमेंट्स वाली पोस्ट को देखते तो हज़ारों है मगर लाईक और कमेंट्स में उनकी नानी परलोक सिधार जाती है। ये लाईक कमेंट्स भी कुछ लोगयारी दोस्ती निभाने में करते है, कमेंट्स आये भी तो इमोजी जिन्दाबाद। मिलने पर कोई कोई दरियादिल अप्रत्यक्ष रूप से ये बताने में गुरेज नहीं करते है कि उनकी निगाहें आपकी हर गतिविधि पर है।

वरिष्ठ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने साठ के दशक में एक साक्षात्कार में कहा था- हमारे लिखे से कुछ नहीं होता है। ग़ालिब से लेकर प्रभु जोशी तक और अनेक ख्यातनाम रचनाकारों का लिखे और सामने आए से ज्यादा लिखा लेखन भी वक्त के दरिया में बह गया। आज कई कई किताबों के लेखक को भी लोग लेखक मानकर राजी नही हैं। ऐसे में किसी गुमान में रहे बगैर सोचे जो है बेहतर है जो नहीं वो उससे बेहतर है। दरअसल आपके अपने चहेते और अपनी कही जाती दुनिया आपको और आपके लेखन को ठेंगे पर रखते है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? आज आप देश के बड़े से बड़े अखबार में छप लीजिए या विदेश की किसी पत्र-पत्रिका में। कहीं भी पुरस्कृत या सम्मानित हो लीजिए। कोई धेले को कोई नही पूछेगा क्योंकि आज हर कोई तो बकरे बकरियों की तरह मैं-मैं करता मिमियाने में लगा है। लोग एड़ियां ऊंची कर कद बढ़ाना चाहते हैं। चांद पर थूक कर सेल्फी ले रहे हैं। इसलिए कोई भ्रम न पालें - दो रोटी ज़्यादा खा लें। व्यस्त रहें -मस्त रहें।

अनियंत्रित भीड़ ने बदली मूल अवधारणा

तीर्थ पर्यटन

प्रयाग पाण्डे

लेखक नैनीताल निवासी हैं।

यूँ तो विश्व में तीर्थाटन का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में तीर्थ और पर्यटन का घनिष्ठ संबंध रहा है। यहाँ तीर्थाटन एवं धार्मिक पर्यटन की प्राचीन परंपरा है। प्राचीनकाल में पर्यटन की शुरुआत तीर्थाटन, व्यावसायिक एवं साहसिक यात्राओं से ही हुई थी। उस दौर में तीर्थ यात्रा की भावना मन और विचारों की पवित्रता से जुड़ी थी। श्रद्धालु शांति की खोज, पापों के प्रायश्चित और निर्वाण के निमित्त तीर्थयात्राएं किया करते थे। तीर्थयात्रियों को तीर्थ स्थलों में मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती थी। तीर्थाटन को सांसारिक परेशानियों एवं चिंताओं से मुक्ति पाने का उपक्रम माना जाता था। तब तीर्थ यात्राओं के लिए न्यूनतम सुविधाओं की आवश्यकता होती थी। तीर्थ यात्रा साधना के समतुल्य मानी जाती थी। श्रद्धालु कठिनतम तीर्थ यात्राएं किया करते थे। तब तीर्थ यात्रा के संबंध में कहा जाता था- 'जितनी कठिन यात्रा, उतना ही उत्तम फल।'

आज के दौर में मानव जीवन में व्यापारीकरण और भौतिकवाद बढ़ता चला जा रहा है। विलासप्रियता के चलते अब तीर्थ एवं धार्मिक पर्यटन में भी आनंद एवं आराम की चाहत होने लगी है। जिसके कारण तीर्थाटन एवं धार्मिक पर्यटन का मूल आधार तेजी से बदल रहा है। आधुनिक युग में तीर्थ भी 'सर्वसुविधायुक्त आनंददायक यात्रा' हो गई है। धर्म स्थलों की यात्रा का प्रेरक तत्व धर्म से अधिक देखादेखी, मौजमस्ती और सैर-सपाटा हो गया है।

धर्म स्थलों में आस्था के नाम पर उमड़ने वाली अनियंत्रित भीड़ के कारण पारिस्थितिकी संतुलन गड़बड़ाने लगा है। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। भीड़भाड़ और कोलाहलपूर्ण वातावरण से नाजुक पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। स्थानीय संशाधनों में अत्यधिक दबाव पड़ने लगा है। आए दिन लगने वाले वाहनों के लंबे जाम के कारण स्थानीय निवासियों की दैनंदिन की गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होने लगी हैं। आवागमन पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा है। धर्म स्थलों की वहन क्षमता से कई गुना अधिक लोगों के आने से धर्म स्थलों की पचाने की क्षमता क्षीण होने लगी है। चकाचौंध कर देने वाले अल्पावधि के इस अनियंत्रित पर्यटन के कारण संवेदनशील एवं चैतन्य पर्यटकों का आगमन कम होने लगा है। जिससे टिकाऊ और लाभकारी पर्यटन प्रभावित हो रहा है।

यह स्थापित सत्य है कि अनियंत्रित एवं अनियोजित पर्यटन से लाभ के बजाय हानि अधिक होती है। अल्पकालिक सैर- सपाटा पर्यटन से लाभ नहीं, बल्कि विशुद्ध हानि ही होती है। ऐसे पर्यटन से भौतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं कानून-व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग को टिकाऊ, दीर्घजीवी और लाभकारी बनाना है तो पर्यटकों की संख्या पर अंकुश लगाना आवश्यक है, भले ही वह धार्मिक या तीर्थ पर्यटन ही क्यों न हो।

क्या हमारी हँसी किसी की गरिमा को कम कर रही है?

गरिमा बनाम मनोरंजन

मनीषा मंजरी

लेखक उपन्यासकार हैं।

हँसी मनुष्य की सबसे सहज और सुंदर अभिव्यक्तियों में से एक मानी जाती है। एक शिशु की खिलखिलाहट से लेकर जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी चेहरे पर आ जाने वाली हल्की मुस्कान तक, हँसी हमें मनुष्य बनाती है। यह तनाव कम करती है, संबंधों को सहज बनाती है और जीवन की कठोरताओं के बीच राहत का एक क्षण प्रदान करती है। किंतु क्या हर हँसी समान रूप से निर्मल होती है? क्या हर ठहाका उत्सव का प्रतीक होता है?

हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हँसी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रही; वह एक सामाजिक वक्तव्य बन चुकी है। कुछ सेकंड की रील, एक वायरल क्लिप, किसी स्टैंड-अप शो का छोटा-सा अंश, और लाखों लोग उस पर हँसते हैं, उसे साझा करते हैं, उसके संवाद दोहराते हैं। लेकिन कभी-कभी इस सामूहिक हँसी के बीच एक असुविधाजनक प्रश्न सिर उठाता है, क्या हमें उस हँसी की प्रकृति पर विचार नहीं करना चाहिए, जो किसी दूसरे की गरिमा की कीमत पर पैदा होती है?

कॉमेडी और व्यंग्य का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है। सत्ता के दंभ को तोड़ने, सामाजिक पाखंडों को उजागर करने और स्थापित मान्यताओं पर प्रश्न उठाने का साहस हास्य ने बार-बार दिखाया है। कई बार एक व्यंग्यकार वह सच कह देता है, जिसे गंभीर भाषण भी प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए यह कहना गलत होगा कि हास्य को सीमाओं में बाँध देना चाहिए या कलाकारों को केवल सुरक्षित विषयों तक सीमित कर देना चाहिए। लेकिन प्रश्न विषय का नहीं, दृष्टि का है।

एक हँसी वह होती है जो अन्याय पर चोट करती है। वह अहंकार का उपहास उड़ाती है, व्यवस्था की विसंगतियों को उजागर करती है और हमें स्वयं पर हँसना सिखाती है। दूसरी हँसी वह होती है जो किसी की असहायता, पहचान, शरीर, सहमति, पेशे या गरिमा को निशाना बनाकर पैदा होती है। पहली हँसी समाज को अधिक मानवीय बनाती है; दूसरी धीरे-धीरे हमारी संवेदनशीलता को क्षीण कर देती है।

डार्क कॉमेडी साहित्य और कला का एक स्थापित रूप है। उसने युद्ध, मृत्यु, राजनीतिक हिंसा और मानवीय त्रासदियों पर भी कटाक्ष किया है। प्रश्न यह नहीं है कि विषय कितना अंधकारमय है। प्रश्न यह है कि उस अंधकार में हमारी नैतिक स्थिति क्या है। हम किसके साथ खड़े हैं? पीड़ित के साथ या पीड़ा को मनोरंजन में बदल देने वालों के साथ? जब किसी महिला की सहमति को मज़ाक में बदल दिया जाता है, जब किसी पुरुष की भावनाओं का उपहास सामान्य मान लिया जाता है, जब किसी मृत शरीर के प्रति सम्मान को हास्य का विषय बना दिया जाता है, तब हमें यह पूछना चाहिए कि आखिर हम किस बात पर हँस रहे हैं। क्या हम किसी विचार की मूर्खता पर हँस रहे हैं, या किसी मनुष्य की गरिमा के क्षरण पर?

समाज की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक यह है कि वह धीरे-धीरे असंवेदनशील होता जाता है। जो बात पहले हमें असहज करती थी, वही बार-बार सुनने के बाद सामान्य लगने लगती है। हम कहते हैं,'अरे, मज़ाक था।' हम कहते हैं, 'इतना भी गंभीर मत बनो।' लेकिन इतिहास गवाह है कि बहुत-सी अमानवीय धारणाएँ पहले चुटकुलों के रूप में ही स्वीकार की गई थीं। पूर्वाग्रह अक्सर हँसी का मुखौटा पहनकर आते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं कि हर विवादास्पद मज़ाक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या हर कलाकार को कठघरे में खड़ा कर दिया जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है। कलाकारों को प्रयोग करने, सीमाओं को परखने और प्रश्न उठाने का अधिकार है। लेकिन दर्शकों को भी उतना ही अधिकार है कि वे कह सकें, 'यह हमें स्वीकार नहीं है।'

उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वे एक-दूसरे के पूरक हैं। किसी मंच पर कही गई बात केवल मंच तक सीमित नहीं रहती। वह विचार बनती है, विचार व्यवहार बनता है और व्यवहार सामाजिक संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। इसलिए सार्वजनिक आलोचना का उद्देश्य केवल दंड नहीं होना चाहिए; उसका उद्देश्य संवाद, आत्ममंथन और सुधार भी होना चाहिए।

शायद हमें अपने बच्चों को यह सिखाने की आवश्यकता है कि बुद्धिमत्ता और क्रूरता एक ही चीज़ नहीं हैं। किसी का अपमान कर देना हास्य नहीं है। किसी की गरिमा की कीमत पर लोकप्रिय हो जाना प्रतिभा नहीं है। सबसे कठिन और सबसे सुंदर हास्य वही है जो बिना किसी को छोटा किए भी गहरी बात कह सके।

आज जब हम किसी वायरल क्लिप पर हँसते हैं, किसी मंचीय प्रस्तुति पर तालियाँ बजाते हैं या किसी चुटकुले को आगे बढ़ाते हैं, तब हमें स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, क्या यह हँसी किसी मनुष्य की गरिमा को कम कर रही है? क्योंकि किसी समाज का चरित्र केवल उसके कानूनों से निर्धारित नहीं होता, उसकी हँसी से भी पहचाना जाता है। और शायद हमारे समय का सबसे आवश्यक प्रश्न यही है, क्या हमें उस हँसी की प्रकृति पर विचार नहीं करना चाहिए, जो किसी दूसरे की गरिमा की कीमत पर पैदा होती है? यदि इस प्रश्न का उत्तर 'हाँ' है, तो संभव है कि हम केवल बेहतर दर्शक ही नहीं, बल्कि बेहतर मनुष्य भी बन सकें।

श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, इंदौर में 24 जून को हो रहा है यह गरिमामय आयोजन

नवाचार, सतत विकास एवं वैश्विक साझेदारी के माध्यम से भविष्य का रूपांतरण विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

सुबह सवेरे संवाददाता। श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, इंदौर में 24 जून को प्रातः 10:30 बजे महाविद्यालय परिसर में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है,जिसमें अतिथि पुष्यमित्र भार्गव, महापौर, इंदौर नगर निगम, डॉ.राजेश वर्मा,कुलगुरु,रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर , डॉ. सचिन शर्मा, डी.सी., डी.सी. (डी.ए.वि.वि.) उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में डॉ. दिनेश दवे, ओ.एस.डी., उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल एवं डॉ. अनुराग द्विवेदी सह कुलसचिव (डी.ए.वि वि) समापन सत्र में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में पुरुषोत्तमदास पसारी, कुलाधिपति, श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर एवं अन्य प्रबंधन वर्ग भी उपस्थित रहेंगे। इस क्रम में कार्यक्रम में ऑनलाइन मंच के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अतिथि डॉ. रानिया लैम्पू (ग्रीस), डॉ. अरुस्यक इवान्यन (अमेरिका), प्रो.

क्रिस्टीना मौरिसियो (मेक्सिको) एवं प्रो. सापकोटा प्रदीप (नेपाल) उपस्थित रहेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. परितोष अवस्थी ने बताया कि सम्मेलन में नवाचार, सतत विकास, वैश्विक सहयोग तथा समकालीन चुनौतियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा। संगोष्ठी में देश-विदेश के शिक्षाविदों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं विषय-विशेषज्ञों की सहभागिता रहेगी। यह अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी भारत सरकार के 'विकसित भारत 2047' के विज़न तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की भावना के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। संगोष्ठी में नवाचार, सतत विकास, हरित प्रौद्योगिकी एवं वैश्विक सहयोग से जुड़े विषयों पर मंथन होगा। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर, नवाचारी एवं सतत विकास आधारित भारत के निर्माण के संकल्प को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। संगोष्ठी में प्राप्त शोध निष्कर्ष एवं सुझाव शिक्षा, उद्योग, नीति-निर्माण तथा स्मार्ट एवं सतत शहरों के विकास में उपयोगी सिद्ध होंगे। समिति के संयोजक प्रो. विभोर ऐरन एवं डॉ. मनीष दुबे ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं एवं उद्योग जगत के विशेषज्ञों के मध्य संवाद को प्रोत्साहित करना तथा नवाचार एवं सतत विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना है।

महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, सचिव महेश चिमनानी ने सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु अपनी अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 1912 की विशेष सुविधा

अब बिल, मीटर और इंस्टॉलेशन से जुड़ी दिक्कतों का 1912 पर घर बैठे होगा समाधान

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की सुविधा और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी द्वारा कार्यक्षेत्र में लगाए जा रहे आधुनिक स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 पर विशेष शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की गई है। अब उपभोक्ता स्मार्ट मीटर से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए सीधे इस नंबर पर संपर्क कर निराकरण करा सकते हैं।

इन शिकायतों का होगा निराकरण– कंपनी द्वारा शुरू की गई इस सुविधा के अंतर्गत स्मार्ट मीटर उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल करके स्मार्ट मीटर का अनुचित तरीके से इंस्टॉलेशन होना, स्मार्ट मीटर का जल जाना, डिस्प्ले बंद होना या मीटर का क्षतिग्रस्त होना, मासिक बिजली बिल का जनरेट न होना, गलत बिल जनरेशन की समस्या, बिल में एक्सपोर्ट यूनिट्स का गलत दर्ज होना, मीटर की तेज रिकॉर्डिंग के कारण बिजली का अधिक बिल आने संबंधी शिकायत, उपाय एप में स्मार्ट मीटर का डाटा गलत दिखना या प्रदर्शित न होना, बिजली बिल में मीटर का गलत सीरियल नंबर अंकित होना, नए स्मार्ट मीटर की स्थापना के समय प्रारंभिक (शुरुआती) रीडिंग में विसंगति होना, सोलर/नेट मीटर में परिवर्तित न होना, बिल भुगतान करने के बाद भी बिजली का रीकनेक्शन न किया जाना, नए स्मार्ट मीटर की स्थापना के समय पुराने मीटर की आखिरी रीडिंग गलत दर्ज होना तथा चेक मीटर लगाने का अनुरोध करना या अनुरोध के बावजूद चेक मीटर इंस्टॉल न होने संबंधी शिकायतों का निराकरण करा सकेंगे।

स्मार्ट मीटर पूरी तरह सुरक्षित और सटीक

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बताया है कि केन्द्र सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के तहत कंपनी द्वारा पूरे कार्यक्षेत्र में अब तक 10 लाख 86 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, सटीक बिलिंग और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने का काम समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कंपनी की टीमें लगातार कार्य में जुटी हुई हैं। यदि किसी उपभोक्ता को मीटर की कार्यप्रणाली, बिलिंग या इंस्टॉलेशन को लेकर कोई भी शंका या समस्या है, तो वे बिना किसी झिझक के टोल-फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज होते ही संबंधित तकनीकी टीम द्वारा प्राथमिकता के आधार पर समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा

बिजली बिल कम करने तथा खपत को नियंत्रित करने में मददगार साबित हुआ स्मार्ट मीटर

ग्राहकों के लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की पहल

भोपाल। केन्द्र सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र में स्मार्ट मीटर बेहतर कार्य कर रहे हैं। जहां-जहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां पर समय पर बिलिंग तथा रीडिंग हो रही है। कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में अब तक 10 लाख 86 हजार 171 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। कंपनी ने कहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, सटीक बिलिंग और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने का काम समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कंपनी की टीमें लगातार कार्य में जुटी हुई हैं।

रीडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं– मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्रांतर्गत जब से स्मार्ट मीटर स्थापित करने शुरू किये हैं तभी से स्मार्ट मीटर के समारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। उपभोक्ताओं को वास्तविक समय में ऊर्जा खपत की सटीक तथा अद्यतन जानकारी मिल रही है, साथ ही रीडिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के परिसर में जाकर रीडिंग लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि निर्धारित तिथि पर ऑटोमेटिक रीडिंग करके उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल पर बिल जारी किया जा रहा है।

एक जिला एक उत्पाद के तहत

धार की पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग (बाग प्रिंट) और प्राकृतिक रंगों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार

धार। मध्य प्रदेश शासन की एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों के ब्रांड निर्माण, विपणन संवर्धन और व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा एक अनूठा राज्यव्यापी सोशल मीडिया जागरूकता एवं प्रचार अभियान शुरू किया जा रहा है। इस व्यापक अभियान के केंद्र में जिला धार का गौरव और विश्वप्रसिद्ध जी.आई. टैग्ड उत्पाद बाग प्रिंट रहेगा।

अभियान के उद्देश्य-

वैश्विक पहचान और ब्रांडिंग: धार के प्रसिद्ध जी.आई. टैग्ड बाग प्रिंट की विशिष्ट पहचान को राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से स्थापित करना तथा इसकी प्रामाणिकता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना है।

कला और तकनीक का संवर्धन: बाघ प्रिंट की पारंपरिक हस्तनिर्मित ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक, प्राकृतिक रंगों के उपयोग और शिल्प कौशल को बढ़ावा देकर धार जिले को हस्तशिल्प एवं वस्त्र कला के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है।

डिजिटलीकरण और नए बाजार: स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को सीधे नए बाजारों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, डिजिटलीकरण और सीधे निर्यात के अवसरों से जोड़ना है।

लघु एवं मध्यम उद्यमों और निवेश को बढ़ावा: हस्तशिल्प आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, मूल्य संवर्धन गतिविधियों, डिजाइन नवाचार और पैकेजिंग को प्रोत्साहित करना है ताकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ़ हो सके।

रोजगार और आत्मनिर्भरता: इस पहल के माध्यम से वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को सशक्त करते हुए हस्तशिल्प क्षेत्र में निवेश, कौशल विकास, रोजगार सृजन और सतत आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करना है, जिससे स्थानीय कारीगर समुदाय की आय में वृद्धि हो और जिले के आर्थिक विकास को नई गति मिल सके।

नवागत जिला कोषालय अधिकारी आस्था चौरसिया ने पदभार ग्रहण किया

धार। जिला कोषालय कार्यालय में सोमवार को एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, नवागत जिला कोषालय अधिकारी आस्था चौरसिया ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया तथा सफल कार्यकाल की शुभकामनाएँ दीं। कार्यक्रम में पूर्व जिला कोषालय अधिकारी मान सिंह डामोर को पदोन्नति उपरांत डीडीवीएस संचालनालय, भोपाल में स्थानांतरण होने पर विदाई दी गई। डामोर ने धार जिले में अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता एवं कर्मचारी हितों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए, जिनकी सभी ने सराहना की। अपने उद्बोधन में आस्था चौरसिया ने कहा कि वे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से कोषालय की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं जनहितैषी बनाने का प्रयास करेंगी। वहीं मान सिंह डामोर ने धार में मिले सहयोग और स्नेह के लिए समस्त कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सहायक कोषालय अधिकारी प्रकाश बड़ोले सहित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने डामोर के उज्ज्वल भविष्य एवं आस्था चौरसिया के सफल कार्यकाल की शुभकामनाएँ दीं।

कालातीत ऋण वसूली एवं नवीन सदस्यता अभियान अंतर्गत

नवीन सदस्य बनाये जाने हेतु शाखा प्रबंधकों को दिए निर्देश

धार। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक धार में बैंक के समस्त क्षेत्राधिकारीयों एवं शाखा प्रबंधकों की मासिक समीक्षा बैठक मुख्यालय सभाकक्ष मे सम्पन्न हुई। बैंक मुख्य कार्यपालन अधिकारी के.के. रायकवार द्वारा सर्वप्रथम म.प्र. शासन द्वारा घोषित कृषि कल्याण वर्ष 2026 अंतर्गत बी-पैक्स संस्थाओं में अधिक से अधिक नवीन सदस्यता अभियान अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। उक्त अभियान के अंतर्गत जिला बैंक धार द्वारा 9668 से अधिक नवीन सदस्यों को संस्था में सदस्यता ग्रहण कर पैक्स में जोड़ा गया तथा 30 जून 2026 तक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य करने के निर्देश बैठक में उपस्थित समस्त क्षैत्राधिकारियों शाखा प्रबंधकों को दिये गये है। संस्था के चालू ऋणों की शेष रहे सदस्यों की ऋण वसूली हेतु व्यक्तिगत संपर्क कर ऋण जमा करने हेतु समझाईश देने का अभियान चलाये जाने एवं शाखा प्रबन्धक के साथ-साथ समस्त क्षैत्राधिकारी भ्रमण पर जाकर सदस्यों से संपर्क स्थापित किये जाने तथा उन्हें ऋण जमा कर शासन की 0 (शून्य) प्रतिशत ब्याज दर पर योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अग्रिम खाद उठाने हेतु किसानों को अवगत कराने, खरीफ ऋण वितरण, कृषि ऋणों की मांग/वसूली, धारा 85 में कार्यवाही, क्रिश योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाकर नियत समयावधि में कार्य करने हेतु निर्देशित किया।

अमलतास विशेष विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

देवास। अमलतास विशेष विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, शिक्षकों एवं स्टाफ सदस्यों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम Yoga for Healthy Ageing (स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन के लिए योग) रही।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना एवं योग के महत्व पर संक्षिप्त संबोधन के साथ हुआ। प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को उनकी क्षमतानुसार सरल योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया। बच्चों ने पूरे उत्साह एवं अनुशासन के साथ भाग लिया तथा योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने का संदेश दिया।

इस अवसर पर चेयरमैन महोदय श्री मयंक राज सिंह भदौरिया ने अपने संदेश में कहा कि 'योग स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का आधार है। विशेष बच्चों के सर्वांगीण विकास में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। '

विद्यालय की प्राचार्या डॉ. भारती लाहोरिया ने अपने संदेश में कहा कि 'नियमित योग बच्चों में आत्मविश्वास, एकाग्रता एवं सकारात्मक सोच का विकास करता है। योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर हम बेहतर स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। 'कार्यक्रम के दौरान योग गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार वितरित किए गए। बच्चों ने पुरस्कार प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नियमित रूप से योग करने का संकल्प लिया।

बिजली विभाग में हो गई 'महाचोरी'

13 खंभे और तीन किलोमीटर लंबी 11 केवी की लाइन रहस्यमयी तरीके से गायब

उमरिया (नप्र)। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बिजली विभाग में महाचोरी हो गई है। अमरपुर क्षेत्र में बिजली विभाग की संपत्ति चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्रामीण इलाके में बिछी 11केवी विद्युत लाइन से करीब तीन किमी लंब तार गायब है। साथ ही बिजली आपूर्ति के लिए लगाए गए 13 खंभे भी लापता हो गए हैं। चोरी की घटना ने स्थानीय प्रशासन को सकते में डाल दिया है।

13 खंभे भी रहस्यमयी तरीके से गायब– मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। ग्राम सुखदास हाई स्कूल रोड के पास विद्युत आपूर्ति के लिए रखे गए 13 बिजली पोल भी गायब पाए गए। विभाग ने इन पोलों की कीमत लगभग 32 हजार 500 रुपए बताई है। इस तरह कुल मिलाकर विभाग को करीब 2 लाख 32 हजार 500 रुपये का नुकसान हुआ है।

निजी कंपनी पर है शक– वहीं, सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि शिकायत में कनिष्ठ अभियंता ने एक निजी कंपनी के कार्य से जुड़े व्यक्ति पर शक जताया है। आवेदन में कहा है कि बरही से महरोई मोड़ के बीच 33 केवी विद्युत लाइन का कार्य चल रहा है। इसी कार्य से जुड़े व्यक्ति पर संदेह व्यक्त किया गया है। हालांकि अभी तक किसी की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह केवल शिकायतकर्ता द्वारा व्यक्त किया गया संदेह है।

मामले की जांच शुरू

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर लाखों रुपये की विद्युत सामग्री कैसे गायब हुई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। कनिष्ठ अभियंता ने बताया विभाग की विद्युत सामग्री चोरी हुई है, जिसकी शिकायत अमरपुर चौकी में दर्ज करा दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग की सामग्री की सुरक्षा को लेकर यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर तीन किलोमीटर लंबी विद्युत तार और 13 पोल जैसी भारी सामग्री बिना किसी की नजर में आए कैसे गायब हो गई। यह सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।

अमरपुर चौकी में दर्ज कराई एफआईआर

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ अभियंता अवनीश कुमार मिश्रा ने अमरपुर चौकी में एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि ग्राम बड़छड़ क्षेत्र में 11 केवी कृषि फीडर लाइन की तार अज्ञात लोगों द्वारा काटकर चोरी कर ली गई है। विभाग के अनुसार चोरी हुई एएएसी रैबिट कंडक्टर तार की लंबाई लगभग तीन किलोमीटर है, जिसकी कीमत करीब दो लाख रुपये आंकी गई है।

विश्व संगीत दिवस पर सजी गीतों की महफ़िल

देवास। शहर के प्रसिद्ध लव कुश सुर संगम ग्रुप द्वारा विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में शानदार सुरमयी शाम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ नागरिक संस्था के सचिव गंगासिंह सोलंकी, ज्योति दुबे, प्रदीप शुक्ला, प्रीति चौधरी एवं श्रीमती धवळे द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रानी सोलंकी द्वारा सरस्वती वंदना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महू से पधारी सारा म्यूजिकल ग्रुप की डायरेक्टर चंदा कुंडलवाल का ग्रुप के सदस्यों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने सुमधुर गीतों की प्रस्तुति दी। उनके युगल गीतों में साथ देने वाले ग्रुप के संचालक अनिल नायक, सह संचालक रामजीत सिंह, जयंत रेडेकर,संतोष शर्मा रहे। उनके साथ गीतों की प्रस्तुति सुनकर उपस्थित सिंगर साथी एवं श्रोता गीतों मे मदमस्त हो गए। प्रस्तुति देने वाले अन्य सिंगर प्रीति चौधरी, अमोल मोरे इंदौर, मोहन शर्मा, रानी सोलंकी, गणेश तंवर, प्रदीप शुक्ला, विलास तेलंग, रवि अग्रवाल, मनीष जैन, हरीश जैन, डी के यादव, के सी नागर, राजेंद्रपाल सिंह, नीरज सेंगर, ज्योति दुबे, संतोष दरकदार ने शानदार सुमधुर गीतों की प्रस्तुतियां दी। अजय सोलंकी गुरुजी, वरिष्ठ पत्रकार मोहन वर्मा, विवेक ढवले, आनंदीलाल राठौर, म प्र वि म.पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकमसिंह सायल, सुधि श्रोतागण की उपस्थिति से कार्यक्रम में चार चांद लग गए। श्रोताओं ने सभी के गीतों को बहुत सराहा। सिंगर, कवयित्री और उत्कृष्ट एंकर प्रीति चौधरी ने कार्यक्रम का संचालन कवितामयी अंदाज में किया और लोगों का दिल जीत लिया । यहाँ यह बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि संगीतमय संध्या के कलाकारों को सुनने के लिए, दिल्ली इंदौर उज्जैन पूना, त्रिपुरा आदि स्थानों से संगीत प्रेमी जुड़े रहे जो दूर बैठकर भी सभी के गीतों का आनंद लेते रहे। अंत में ग्रुप के सह-संचालक रामजीतसिंह द्वारा आभार व्यक्त किया गया। विशेष संगीत दिवस की शाम का आनंदमयी कार्यक्रम संपन्न हुआ।

कला-साधना और सांस्कृतिक सौंदर्य से सराबोर रही संगीत दिवस की संध्या

विश्व योग एवं संगीत दिवस के अवसर पर शासकीय संगीत महाविद्यालय में आयोजित हुई संगीत सभा

धार। विश्व योग एवं संगीत दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के सौजन्य से शासकीय संगीत महाविद्यालय धार द्वारा संगीत सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, कला और परंपराओं से जोड़ना एवं उनमें सांस्कृतिक चेतना का संवर्धन करना रहा । घोड़ा चौपाटी स्थित शासकीय ललित कला महाविद्यालय में आयोजित संगीत संध्या ने कला प्रेमियों को भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपराओं की अनुपम अनुभूति कराई । महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती कांति तिर्की ने उपस्थित अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम का आगाज़ महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना गाकर किया गया।

संगीत संध्या में पहली प्रस्तुति संगीत महाविद्यालय की ही शास्त्रीय संगीत की बारीकियों एवं घरानेदार परंपराओं की अध्यनरत छात्रा यशस्विनी मुरमकर द्वारा शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी गई, जिसमें छात्रा ने राग यमन में बड़ा ख्याल एवं छोटा ख्याल आलाप-तान तथा एक भजन गाकर गुरु-शिष्य परंपरा एवं संगीत-साधना को भावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त किया। इनके साथ महाविद्यालय के छात्र तबले पर योगी पवार तथा हारमोनियम पर आदित्य प्रताप ठाकुर ने सुंदर ढंग से संगत की।

तत्पश्चात भोपाल के सुप्रसिद्ध युवा तबला वादक अंशुल प्रताप सिंह, अपने दादा गुरु प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्व. ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जी की तीसरी पीढ़ी का निर्वाह करते हुए बनारस घराने के प्रसिद्ध युवा तबला वादक हैं उन्होंने विभिन्न लयों में तबला वादन कर दर्शकों को लय और ताल की अद्भुत अनुभूति कराई ।उन्होंने अपने तबला वादन की शुरुआत प्रसिद्ध ताल तीन ताल से की।

संगीत सभा की अंतिम प्रस्तुति में इंदौर की गुणी गायिका रसिका गावड़े ने अपने सुमधुर सधे हुए सुरों में आध्यात्मिकता और भक्ति के स्वरों से शाम को सजाया । उन्होंने अपनी सुरमई प्रस्तुति की शुरुआत राग मारूबिहाग से किया । इस रात की गरिमा और माधुर्य को स्वर देते हुए एक ताल में निबद्ध बड़ा ख्याल एवं तीन ताल में छोटा ख्याल तथा नाट्यगीत और अंत में राग भैरवी में मीरा के भजन प्रस्तुत किया । उनकी गायकी में रागों की शास्त्रीय गंभीरता और भावों की सहज अभिव्यक्ति श्रोताओं को एक विशिष्ट संगीतानुभूति प्रदान कर रही थी । साथ ही तबले और हारमोनियम की अर्थपूर्ण संगत से लय और स्वर के अद्भुत समन्वय का सृजन परिलक्षित हुआ। अपनी प्रस्तुति का भावपूर्ण समापन राग भैरवी में सुंदर भजन से किया,जो कि भक्ति, माधुर्य और गुरु-परंपरा के प्रति उनकी श्रद्धा का सुंदर प्रतीक था । इस संगीत संध्या में उनके साथ हारमोनियम पर दीपक खलतकर एवं तबले पर अनूप राजे पवार ने संगत दी। स्वरलय और भाव के अद्भुत समन्वय से सुसज्जित यह प्रस्तुति भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा सौंदर्य और आध्यात्मिक संवेदना का अनुपम उत्सव सिद्ध होता नजर आया।उत्कृष्ट तबला वादन एवं गायन प्रस्तुतियों ने वातावरण को कला-साधना और सांस्कृतिक सौंदर्य से सराबोर कर दिया। विश्व संगीत दिवस पर आयोजित यह संध्या भारतीय शास्त्रीय कलाओं की समृद्ध विरासत, सृजनात्मकता और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध हुई। अंत में कलाकारों का स्वागत-सत्कार महाविद्यालय की प्राचार्य कांति तिर्की द्वारा शॉल-श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया । कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन प्रिया शर्मा द्वारा किया गया। शा.संगीत तथा ललित महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थीगण, स्टाफ सदस्य- सोमत सिंह, रविंद्र रोडवे, शशि चौधरी, देशराज वशिष्ठ, पंकज राठौर, प्रेम सिंह सिकरवार, दुर्गेश बिरथरे, नवनीत लोकरे, भूपेंद्र सिंह चौहान, नंदिनी खरमले, उदय ,पियूष ,पवन , गोपाल, गिरधारी, सुधि श्रोताओं एवं दर्शक दीर्घा में प्रमुख रूप से वरिष्ठ संगीतज्ञ लक्ष्मीकांत जोशी ,वृषाली देशमुख, दीपक खरतकर तथा शहर के गणमान्य श्रोतागण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

सोने का खोया गले का हार मिला ,खुश हुई महिला

सोहागपुर। मंगल भवन पार्क में बच्चों को घुमाने गई रिंकी पटेल पति पुष्पराज पटेल निवासी गुर्जरखेड़ी तहसील सोहागपुर जिसके गले का हार सोने की मनचली हार वजन करीब 1.5 तोला टूटकर पार्क में गिर गई थी। इसकी सूचना थाना में दी । थाना सोहागपुर पुलिस टीम ने अपनी सुझ बूझ से तलाश किया । पुलिस को जानकारी मिली उक्त आभूषण पार्क में काजल दोहरे निवासी आंबेडकर वार्ड सोहागपुर को मिला है । वह खोई हुई सोने की मनचली पुलिस द्वारा फारियादिया को दिलाई गई। महिला अपना आभूषण मिलने से प्रसन्न होकर पुलिस का आभार व्यक्त किया। नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी की सूझबूझ से पुलिस टीम उनि राजेंद्र सिंह कुशवाह सहायक उप निरीक्षक गणेश राय, प्रधानआरक्षक के के ठाकुर ,आर मनोहर दायमा,अफसर खान, महिला आरक्षक नेहा रघुवंशी,मंजू परते आदि ने मंगल भवन पार्क में भूमिका निभाकर फरियादी महिला का आभूषण प्राप्त किया था। हार वर्तमान समय में करीबन दो लाख रुपए से अधिक का था।

संक्षिप्त समाचार

किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदान उपलब्ध कराने सख्त हुआ कृषि विभाग

बैतूल (निप्र)। नवागत उपसंचालक कृषि श्री आर.जी. रजक ने जिला स्तरीय दल के साथ भैंसदेही क्षेत्र के कृषि आदान प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राठौड़ कृषि सेवा केंद्र एवं बालाजी ट्रेडर्स के दुकान और गोदाम की जांच की गई। जांच में बालाजी ट्रेडर्स में उर्वरक एवं कृषि आदानों के भंडारण तथा विक्रय संबंधी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसके चलते संबंधित प्रतिष्ठान के उर्वरकों के विक्रय पर तत्काल रोक लगाते हुए संचालक को कड़ी चेतावनी दी गई। साथ ही प्रतिष्ठान का लाइसेंस निरस्त करने तथा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू की गई। निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से बीज एवं उर्वरक के नमूने भी एकत्र किए, जिन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। उपसंचालक कृषि श्री रजक ने कहा कि किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि आदानों की गुणवत्ता और नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए ऐसे औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे।

कलेक्टर के निर्देशानुसार माखननगर के मुख्य बाजार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार माखन नगर में पिपरिया-नर्मदापुरम मार्ग स्थित मुख्य बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बाजार क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा सड़कों पर सामान रखे जाने तथा अव्यवस्थित वाहन पार्किंग के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा था, जिससे आम नागरिकों एवं वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यातायात व्यवस्था को सुचारु एवं सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस विभाग, राजस्व विभाग तथा स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने सड़क किनारे रखे गए सामान को हटवाया तथा दुकानदारों को भविष्य में सड़क पर सामग्री न रखने एवं निर्धारित स्थानों पर ही व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने की समझाइश दी। प्रशासन द्वारा वाहन चालकों को भी निर्धारित स्थानों पर पार्किंग करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित न हो। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर आगे भी नियमित रूप से अभियान चलाया जाएगा।

जिला न्यायालय परिसर में हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन

नर्मदापुरम (निप्र)। उच्च न्यायालय जबलपुर एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमति तृप्ति शर्मा की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में रविवार 21 जून 2026 को जिला न्यायालय परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त न्यायाधीशगण, समस्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जिला न्यायालय परिसर के साथ केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम् में भी योग शिविर का आयोजन 15 जून 2026 से प्रारंभ किया गया था, उसका समापन रविवार 21 जून 2026 को योग दिवस के अवसर पर किया गया। जिसमें विशेष न्यायाधीश श्री मनोज कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री फिरोज अख्तर, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह सहित समस्त जेल प्रशासन के अधिकारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। योग तनाव और चिंता को कम करता है और मानसिक स्पष्टत लाता है। योग अनुशासन और सकारात्मक आदतों को बढ़ावा देता है।

जिला न्यायालय परिसर में हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन

नर्मदापुरम (निप्र)। उच्च न्यायालय जबलपुर एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमति तृप्ति शर्मा की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में रविवार 21 जून 2026 को जिला न्यायालय परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त न्यायाधीशगण, समस्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जिला न्यायालय परिसर के साथ केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम् में भी योग शिविर का आयोजन 15 जून 2026 से प्रारंभ किया गया था, उसका समापन रविवार 21 जून 2026 को योग दिवस के अवसर पर किया गया।

■ पुलिस परेड ग्राउंड पर सामूहिक योग, विधायक मुकेश टंडन ने स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाने का किया आह्वान

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर विदिशा में उमड़ा जनसैलाब

विदिशा (निप्र)। 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय विदिशा में पुलिस परेड ग्राउंड पर भव्य जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन, कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी तथा योग गुरुओं द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

इसके पश्चात योगाचार्यों के निर्देशन में सामूहिक योगाभ्यास संपन्न हुआ। अपने संबोधन में विधायक श्री मुकेश टंडन ने कहा कि भारत की प्राचीन जीवनशैली और परंपराएं ऐसी थीं जिनमें योग स्वाभाविक रूप से समाहित था। बदलती जीवनशैली और आधुनिक सुविधाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों में तनाव, अवसाद और विभिन्न

स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे समय में योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो अत्यंत व्यस्त दिनचर्या के बावजूद नियमित योगाभ्यास करते हैं और योग के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। योग सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है तथा व्यक्ति को स्वस्थ, सक्रिय और आत्मविश्वासी बनाता है। उन्होंने युवाओं से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य को इससे जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी के लाइव उद्बोधन का सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया गया।

उपस्थित लोगों ने लाइव प्रसारण के दौरान संदेशों को ध्यानपूर्वक सुना। साथ ही योगाचार्यों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम की गतिविधियों का भी लाइव प्रसारण किया गया, जिससे सभी प्रतिभागियों को योगाभ्यास करने में सुविधा हुई।

पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित इस सामूहिक योग कार्यक्रम में विधायक श्री मुकेश टंडन सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सम्पूर्ण कार्यक्रम में उत्साह, अनुशासन और स्वास्थ्य जागरूकता का वातावरण देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन ने योग के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ स्वस्थ एवं निरोगी समाज के निर्माण का संदेश भी दिया। विदिशा जिले में विभिन्न स्थानों पर आयोजित योग कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों लोगों ने योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विदिशा जिले में योगमय रहा वातावरण

● 25 हजार से अधिक लोगों ने किया सहभाग

विदिशा (निप्र)। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज संपूर्ण विदिशा जिला योगमय वातावरण में रंगा नजर आया। जिले के सभी विकासखंडों, जनपद पंचायतों, ग्रामों तथा प्रमुख पर्यटन स्थलों एवं डैमों पर उत्साहपूर्वक योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं, छात्र-छात्राओं, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलेभर में आयोजित विभिन्न योग कार्यक्रमों में 25 हजार से अधिक लोगों ने सहभागिता कर योग के प्रति अपनी आस्था और जागरूकता का परिचय दिया। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया तथा नियमित योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। योग दिवस के अवसर पर जिले के प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। गंजबासौदा स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर, उदयपुर मंदिर परिसर, विदिशा के विश्व प्रसिद्ध उदयगिरि गुफा क्षेत्र, सिरोंज तहसील के देवपुर एवं महामाई मंदिर परिसर सहित अन्य पुरातात्विक स्थलों पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने योगाभ्यास किया।

योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है : राजस्व मंत्री

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिला स्तरीय योग कार्यक्रम आयोजित

▸▸ राजस्व मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने किया सामूहिक योग

सीहोर (निप्र)। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीहोर स्थित आवासीय खेल परिसर में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम आयोजित किया। योग कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा शामिल हुए और योग किया। कार्यक्रम में कोलकाता से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है और योग निरोगी काया का आधार है।

उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। नियमित योगाभ्यास से न केवल शरीर स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहता है, बल्कि मानसिक तनाव भी दूर होता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ जीवनशैली

अपनाने का सबसे सरल एवं प्रभावी माध्यम है। राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज के निर्माण में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा ने भी संबोधित किया। योग कार्यक्रम में कलेक्टर श्री बालागुरू के., एसपी श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना, डीएफओ श्रीमती अर्चना पटेल, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, खिलाड़ी, विद्यार्थी एवं नागरिक भी शामिल हुए और सभी ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर स्वस्थ रहने का संकल्प लिया।

संजय सागर डेम के प्राकृतिक वातावरण में हुआ सामूहिक योगाभ्यास

● स्वस्थ जीवनशैली का दिया संदेश

विदिशा (निप्र)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील अंतर्गत स्थित संजय सागर डेम नेहराई परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य तथा स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ योग दिवस की थीम के अनुरूप स्वस्थ एवं संतुलित जीवन के संदेश के साथ किया गया। प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने प्राणायाम, ध्यान एवं विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। योग विशेषज्ञों ने बताया कि नियमित योगाभ्यास न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक तनाव को दूर कर व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है।

योग व्यक्ति को स्वस्थ, अनुशासित एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। संजय सागर डेम के रमणीय वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को प्रकृति के सान्निध्य में योग करने का अनूठा अनुभव प्रदान किया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से हुई अभिलाषा के गृहस्थ जीवन की शुरुआत

सीहोर (निप्र)। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी और अनूठी योजनाओं में से एक है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक और धूमधाम से कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जहां एक ओर सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से बेटियों का नया जीवन शुरू होता है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को काफी राहत मिल रही है और माता-पिता बेटी के विवाह की चिंता से मुक्त हो रहे हैं।

सीहोर में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीहोर जिले के ग्राम रातिखेड़ा की बेटी अभिलाषा भी परिणय सूत्र में बंधीं। अभिलाषा बताती हैं कि यह योजना उनके जैसी कई बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना के कारण उनका विवाह सम्मानपूर्वक और खुशियों के माहौल में सम्पन्न हुआ। सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता से उन्हें अपने नए गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने में भी

मदद मिलेगी। बेटी अभिलाषा ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना ने गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मान के साथ नया जीवन शुरू करने का अवसर दिया है। यह योजना न केवल बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बना रही है बल्कि समाज में उनके सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक एनसीसी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ

650 कैडेट्स ले रहे सैन्य एवं नेतृत्व प्रशिक्षण

विदिशा (निप्र)। 14 एमपी एनसीसी बटालियन विदिशा द्वारा एसएटीआई एवं एटीआई डिग्री कॉलेज परिसर में 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 19 जून से 28 जून 2026 तक किया जा रहा है। शिविर का संचालन कैंप कमान अधिकारी कर्नल अंशुभान सिंह के नेतृत्व एवं प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सैनी वैद्य की देखरेख में किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ कर्नल अंशुभान सिंह के प्रेरणादायी उद्घाटन संबोधन के साथ हुआ। उन्होंने उपस्थित एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए एनसीसी के मूल मंत्र 'एकता और अनुशासन' के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कैडेट्स को जीवन में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं उनके विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दिया। इस संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में विदिशा एवं रायसेन जिले सहित भोपाल ग्रुप के लगभग 650 एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहे हैं। शिविर के दौरान कैडेट्स को ड्रिल, मैप रीडिंग, योग, नेतृत्व विकास, हथियार प्रशिक्षण, फायरिंग, आपदा प्रबंधन तथा

व्यक्तित्व विकास जैसे विभिन्न विषयों का व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विशेष रूप से शिविर में थल सैनिक कैंप के लिए चयनित भोपाल ग्रुप के लगभग 150 कैडेट्स भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण उन्हें आगामी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं एवं दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित शिविरों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करेगा।

पर्यावरण संरक्षण को भी शिविर की प्रमुख गतिविधियों में शामिल किया गया है। कैडेट्स को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्हें अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचने, संसाधनों की खपत कम करने तथा प्लास्टिक कचरे को एकत्रित कर उसके वैज्ञानिक एवं उचित निष्पादन की जानकारी दी जा रही है। इन गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं में पर्यावरणीय जिम्मेदारी एवं सतत विकास की भावना विकसित करना है। शिविर के दौरान सूबेदार मेजर हृदय रंजन सहित समस्त पीआई स्टाफ एवं एनसीसी अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का संचालन किया। इस अवसर पर कैप्टन रामानंद मिश्रा, लेफ्टिनेंट विनीता प्रजापति, लेफ्टिनेंट मुकेश आजाद, लेफ्टिनेंट राजकमल प्रजापति, चीफ ऑफिसर लखनलाल कुशवाह, सेकंड ऑफिसर रश्मि पाठक, सेकंड ऑफिसर अनिल सोनी, सेकंड ऑफिसर शंकर बहादुर तथा सेकंड ऑफिसर निहाल सिंह रघुवंशी सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

■ किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

23वीं किश्त से विदिशा जिले के 2.31 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

विदिशा (निप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम में देशभर के किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि हस्तांतरित की है ।आज पूरे देश में 'पीएम किसान उत्सव दिवस' के रूप में योजना की 23वीं किश्त का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह महत्वाकांक्षी योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई थी।

योजना के अंतर्गत पात्र कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। प्रत्येक किश्त में किसानों को 2,000 रुपये की

राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि योग्य भूमि धारित करने वाले किसानों की आय में सहयोग करना तथा खेती के लिए आवश्यक निवेश, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनकी खेती की लागत को संतुलित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

कृषि प्रधान भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और खेती-किसानी की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ किया गया।

विदिशा जिले में योजना का व्यापक प्रभाव : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ विदिशा जिले के किसानों को निरंतर प्राप्त हो रहा है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप जिले के हजारों कृषक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विदिशा जिले में 2 लाख 31 हजार 290 पात्र कृषक परिवारों को अब तक योजना की 22 किश्तों के माध्यम से लगभग 871.10 करोड़ रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जा चुकी है। यह राशि किसानों के लिए खेती की आवश्यकताओं की पूर्ति, कृषि निवेश में वृद्धि तथा पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध हुई है। योजना की पारदर्शी व्यवस्था और सीधे बैंक खातों में राशि अंतरण से किसानों को बिना किसी मध्यस्थता के लाभ प्राप्त हो रहा है।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने चीता मित्रों से किया संवाद और चीता संरक्षण की ली जानकारी

भोपाल (नप्र)। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने अपने दो दिवसीय कूनो नेशनल पार्क के प्रवास के दौरान सोमवार को चीता मित्रों से संवाद कर चीता संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा चीतों की सुरक्षा और आमजन के बीच चीतों के व्यवहार को लेकर किये जा रहे जन-जागरूकता के प्रयासों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने सभी चीता मित्रों से वन-टू-वन चर्चा कर परियोजना के लिए उनके द्वारा

राष्ट्रपति ने चीता मित्रों के प्रयासों को सराहा

मानसेवी रूप से किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को चीता मित्रों ने अवगत कराया कि कूनो नेशनल पार्क से लगे सभी ग्रामों में चीता मित्र मौजूद है, जिनके द्वारा चीतो की सुरक्षा के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। चीतों के आबादी क्षेत्र में आवागमन की स्थिति पर किये जाने वाले कार्यों के संबंध में सभी को अवगत कराया गया है। ग्रामीणों को यह जानकारी भी दी जा रही है कि स्वभाविक रूप से चीते किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते है। चीता जब आबादी क्षेत्र अथवा खेतों में दिखाई दे तो तत्काल वन विभाग को अवगत कराया जाये, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुँचे। भारत में चीतों की पुनर्बसाहट के लिए यह परियोजना अति महत्वपूर्ण है।

इस दौरान चीता मित्र श्री कुलदीप आदिवासी सिलोरी, श्री संग्राम आदिवासी एवं कु. राजनदंनी आदिवासी हथेडी, श्रीमती मल्हा आदिवासी सेसईपुरा, श्री शिवम आदिवासी पालपुर, श्री विनोद आदिवासी पैरा, श्री रामलखन आदिवासी कराहल, श्री लालाराम आदिवासी सेसईपुरा, श्री दौलतराम आदिवासी सेसईपुरा और श्री सतीश आदिवासी मोरावन मौजूद रहें।

इस अवसर पर वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री संदीप यादव, पीसीसीएफ श्री शुभरंजन सेन, कमिश्नर श्री सुरेश कुमार, आईजी श्री सचिन अतुलकर, कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा, पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर अग्रवाल, सीसीएफ श्री उत्तम कुमार, डीएफओ श्री आर थिरूकुराल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहें।

उल्लेखनीय है कि कूनो नेशनल पार्क में चीतों की पुर्नस्थापन योजना को लगभग साढ़े तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया है। नेशनल पार्क में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना से चीतों को लाया गया है, वर्तमान में देश में चीतों की संख्या 52 है, जिनमें से 49 चीते कूनो नेशनल पार्क में तथा 03 चीते मंदसौर स्थित गांधी सागर अभ्यारण में मौजूद है। भारत में जन्मे चीतों की संख्या 32 है, चीता प्रोजेक्ट निरंतर सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु चीता मित्रों से संवाद के उपरांत हेलीकॉप्टर से ग्वालियर के लिये रवाना हुई। हेलीपेड पर राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मोनिस्टर इन वेटिंग एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश शुक्ला, सांसद श्री शिवमंगल सिंह तोमर सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने आदरपूर्वक विदाई दी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने ग्वालियर विमानतल पर स्मृति चिन्ह भेंटकर भावभीनी विदाई दी।

भोपाल-उज्जैन में बारिश, छतरपुर में 2 बहनों पर गिरी बिजली

इंदौर-जबलपुर समेत 10 जिलों में चलेगी आंधी, 29 जिलों में बारिश की चेतावनी ; छत्तीसगढ़ पहुंचा मानसून

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में प्री-मानसून की एक्टिविटी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, 22 जून को मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों तक पहुंच गया है। अगले 48 घंटों में मानसून मुंबई समेत इन राज्यों के और अधिक हिस्सों में फैल सकता है।

वहीं सोमवार को भोपाल, धार, रायसेन और उज्जैन में तेज बारिश हुई। अगले कुछ घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्से में बारिश होने का अनुमान है। साथ ही कई जिलों में 26 जून तक हीटवेव (लू), गर्मी और आंधी-बारिश वाला मौसम रहेगा।

वहीं, छतरपुर के बड़ामलहरा के महाराजगंज में बिजली गिरने से आरती अहिरवार (12) की मौत हो गई, जबकि चचेरी बहन झुलस गई। जिला अस्पताल में भर्ती है। बारिश से बचने के लिए दोनों बहनें खेत के पास स्थित एक आम के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गईं। इस दौरान बिजली गिर गई।

मौसम विभाग ने धार के मांडू, देवास, इंदौर, सीहोर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर में 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।

वहीं शिवपुरी, गुना, रतलाम के धोलावाड़, उज्जैन, आगर-मालवा, भोपाल, रायसेन के भीमबेटका और सांची, विदिशा के उदयगिरि, राजगढ़, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी के बावनगजा, खरगोन के महेश्वर, खंडवा के ओंकारेश्वर, बुरहानपुर, नर्मदापुरम् के पचमढ़ी, हरदा, बैतूल, निवाड़ी के ओरछा, दमोह, सागर, सतना के चित्रकूट, मैहर, डिंडौरी, नरसिंहपुर, कटनी, उमरिया के बांधवगढ़, शहडोल, अनूपपुर के अमरकंटक में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

नवाचार से नव निर्माण तक 2.5 वर्षों में लोक निर्माण विभाग की कार्य पद्धति में आया ऐतिहासिक परिवर्तन

सीएम डॉ. यादव के नेतृत्व में तकनीक आधारित सुशासन का मॉडल बना लोक निर्माण विभाग

भोपाल (नप्र)। कभी सड़क और भवन निर्माण तक सीमित समझा जाने वाला मध्यप्रदेश का लोक निर्माण विभाग आज नवाचार, तकनीकी आधुनिकीकरण, पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शिता और जवाबदेही के क्षेत्र में देश के अग्रणी विभागों में अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व तथा लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह के मार्गदर्शन में पिछले 2.5 वर्षों के दौरान विभाग ने केवल अधोसंरचना निर्माण ही नहीं किया, बल्कि कार्यप्रणाली में ऐसे परिवर्तनकारी सुधार लागू किए हैं, जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की स्पष्ट सोच रही है कि विकास केवल निर्माण कार्यों तक सीमित न रहे, बल्कि वह पर्यावरण संरक्षण, जनभागीदारी, तकनीकी दक्षता और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसी सोच को आधार बनाकर लोक निर्माण विभाग ने अनेक अभिनव पहलें शुरू की हैं।

विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का अनूठा मॉडल : लोक कल्याण सरोवर

सड़क निर्माण कार्यों के दौरान आवश्यक मिट्टी एवं मुरम की खुदाई को विभाग ने पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोगी बनाने का अभिनव निर्णय लिया। अब लोक कल्याण सरोवर विकसित किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 में विभाग द्वारा 506 से अधिक लोक कल्याण सरोवर निर्मित किए गए, जिन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ। इन सरोवरों के लिए पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर विशेष डिजिटल मॉड्यूल विकसित किया गया है, जो निर्माण स्थलों के समीप ऐसे स्थानों की पहचान करता है जहाँ वर्षा जल का अधिकतम संचयन हो सके। यह पहल जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन और ग्रामीण समुदायों को दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सड़कों पर लटक रहे मौत के तार

एमपी में हर 8 घंटे में करंट से जा रही एक जान, फिर भी नहीं जाग रहा प्रशासन

भोपाल (नप्र)। एमपी में मानसून जितनी सुस्ती से आ रहा है, सुरक्षा इंतजामों में भी उतनी ही सुस्ती देखने को मिल रही है। सड़कों पर गड्ढों और जलभराव के साथ बिजली के खंभों से लटकते तार भी लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं।

राजधानी में मार्केट हो, कॉलोनी हो या मुख्य सड़क, हर जगह तारों का जाल फैला हुआ है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की चेतावनी का असर भी मानो इन तारों में उलझकर रह गया है और प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रहा।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एमपीईआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 1,963 विद्युत दुर्घटनाएं हुईं। इनमें 1,102 लोगों और 1,492 पशुओं की मौत हुई, जबकि 329 लोग घायल हुए। यानि मध्यप्रदेश में औसतन हर दिन 3 लोगों और हर 8 घंटे में एक व्यक्ति की जान करंट लगने से जा रही है।

न्यू मार्केट में जगह-जगह तार लटक रहे हैं। जहां रोजाना सैकड़ों लोग शॉपिंग करने आते हैं।

पुराने भोपाल की गलियों में लोगों की बालकनी से सटकर तार गुजर रहे हैं।

56 बंगले के पास की मुख्य सड़क पर कई जगह बिजली के तार जमीन को छूते नजर आए।

रोशनपुरा चौराहे पर बिजली के तार खंभे से नीचे जमीन तक लटकते नजर आए।

एमपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई

देश के अलग-अलग कोनों से दबोचे देश विरोधी संदिग्ध, इजहार-उल-हक को रिमांड पर भेजा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश पुलिस की एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड ने देशविरोधी गतिविधियों के संदिग्ध नेटवर्क के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एटीएस ने इस मामले में बिहार से गिरफ्तार किए गए आरोपी इजहार-उल-हक को शनिवार को भोपाल की जिला अदालत में पेश किया। सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की अदालत ने मामले की गंभीरता और आगे की कड़ाई से पूछताछ की जरूरत को देखते हुए आरोपी हक को सोमवार तक के लिए एटीएस की रिमांड पर सौंप दिया है। एटीएस अब आरोपी से उसके नेटवर्क और सहयोगियों के बारे में कड़े सवाल-जवाब कर रही है।

दो आरोपी भेजे गए जेल- इसी मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पकड़े गए नाईम अब्दुल्ला और राजस्थान के अलवर से दबोचे गए शाकिर मेव की पुलिस रिमांड अवधि खत्म होने पर उन्हें भी अदालत के सामने लाया गया था। कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इस पूरी अदालती कार्यवाही के दौरान कोर्ट परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के बेहद कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

अंतरराज्यीय नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा मामला कई राज्यों में फैले एक सुनियोजित नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। भोपाल से शुरू हुई जांच के तार अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों से जुड़ चुके हैं। सोमवार तक मिली इजहार-उल-हक की रिमांड के दौरान एटीएस का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि इस समूह को फंडिंग कहां से हो रही थी और इनके वास्तविक इरादे क्या थे। पुलिस को अंदेशा है कि आने वाले दिनों में इस पूछताछ के आधार पर कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।

इस हाई-प्रोफाइल मामले से जुड़े अब तक के बड़े अपडेट

- एटीएस अधिकारियों के मुताबिक, इस पूरे देशविरोधी नेटवर्क के मामले में अब तक कुल चार गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।
- इस केस में सबसे पहली गिरफ्तारी भोपाल से ही हुई थी, जब मोहम्मद सिराज उर्फ खालिद सैफुल्लाह को पुलिस ने हिरासत में लिया था।
- मोहम्मद सिराज से मिली कड़ियों और इनपुट के आधार पर ही एटीएस ने दूसरे राज्यों में छापेमारी कर जाल बिछाया था।
- इसके बाद पुलिस टीमों ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से क्रमशः नाईम अब्दुल्ला, शाकिर मेव और इजहार-उल-हक को दबोचने में कामयाबी हासिल की।

सिर्फ 'बीमारी छिपाई' कहकर नहीं बचेंगी बीमा कंपनियां

उपभोक्ता आयोग सख्त- क्लेम खारिज करने पर सबूत देना होगा, वर्ना भरना पड़ेगा पूरा पैसा

भोपाल (नप्र)। अब बीमा कंपनियां केवल यह कहकर क्लेम खारिज नहीं कर सकेंगी कि बीमित व्यक्ति ने अपनी पुरानी बीमारी छिपाई है। उपभोक्ता आयोग ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में आरोप लगाने वाली बीमा कंपनी को ठोस सबूत भी पेश करने होंगे, अन्यथा क्लेम रोकना 'सेवा में कमी' माना जाएगा। उपभोक्ता कानून के तहत केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है। कंपनी को दस्तावेजी साक्ष्य के साथ यह साबित करना होता है कि बीमारी पहले से मौजूद थी और उसे जानबूझकर छिपाया गया। बीमा दावा खारिज करने के मामलों में कंपनियों की मनमानी पर भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने सख्त रुख अपनाया है।

स्पोर्ट बाइक से मोबाइल लूटने वाले 4 गिरफ्तार

22 मोबाइल, 4 बाइक और छुरी समेत 11 लाख का मशरूका बरामद

भोपाल (नप्र)। भोपाल की अयोध्यानगर थाना पुलिस ने स्पोर्ट बाइक से मोबाइल लूट और झपटमारी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22 मोबाइल फोन, चार बाइक और एक छुरी समेत करीब 11 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महंगे शौक पूरे करने और जल्दी पैसा कमाने के लिए वारदात करते थे। गैंग के सदस्य खासतौर पर उन लोगों को निशाना बनाते थे, जो सड़क पर चलते समय हाथ में मोबाइल लेकर बात करते थे।

इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में साहिल खान (23), फैजान पठान (21), समीर अंसारी (25) और तालिब खान (28) शामिल हैं। इनके पास से केटीएम ड्यूक, पल्सर 200 एनएस, चोरी की होंडा साइन और R15 बाइक बरामद की गई हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी दो स्पोर्ट बाइक से निकलते थे। आगे चलने वाली बाइक से मोबाइल छीना जाता था, जबकि पीछे वाली बाइक पर साथी बैकअप के लिए रहते थे। विरोध करने पर छुरी दिखाकर मोबाइल लूट लेते थे।11 जून को अयोध्यानगर क्षेत्र के नरेला जोड़ के पास एक युवक से केटीएम बाइक सवार बदमाशों ने छुरी दिखाकर मोबाइल लूटा था। इस घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पूछताछ में आरोपियों ने शहर के अयोध्यानगर, पिपलानी, गोविंदपुरा, हबीबगंज, बागसेवनिया और टीला क्षेत्र की करीब 12 वारदातों का खुलासा किया है।

अखिलेश यादव की बेटी पर भद्दा कमेंट करना पड़ा भारी, रीवा से पकड़ा गया 60 साल का बुजुर्ग

रीवा (नप्र)। जिले से उत्तर प्रदेश की हाई-प्रोफाइल राजनीति और साइबर क्राइम से जुड़ी एक बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी पर सोशल मीडिया पर अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी को रीवा पुलिस ने दबोच लिया है।

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूर्वा कल्याणपुर निवासी नागेश्वर सिंह बघेल (उम्र 60 वर्ष) के रूप में हुई है। मध्य प्रदेश की स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर उत्तर प्रदेश की साइबर सेल टीम को सौंप दिया है।

कानपुर साइबर सेल में दर्ज थी शिकायत- पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी नागेश्वर सिंह बघेल ने इंटरनेट मीडिया पर सपा प्रमुख की बेटी को लेकर बेहद भद्दी और अशोभनीय टिप्पणी की थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर साइबर सेल थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद यूपी पुलिस की तकनीकी टीम और साइबर सेल ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की, तो आरोपी का डिजिटल फुटप्रिंट और मोबाइल लोकेशन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ट्रेस हुई। लोकेशन कन्फर्म होते ही उत्तर प्रदेश साइबर सेल की टीम तुरंत रीवा के लिए रवाना हो गई। यूपी साइबर सेल की टीम ने रीवा पहुंचकर वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और तकनीकी साक्ष्य साझा किए। रीवा पुलिस के निर्देश पर पनवार थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्वा कल्याणपुर गांव में घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया।

रीवा से सीधे कानपुर रवाना हुई टीम

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के आपसी समन्वय के चलते इस कार्रवाई को बेहद गुपचुप और तेजी से अंजाम दिया गया। पनवार थाना पुलिस के सहयोग से आरोपी को कस्टडी में लेने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उसे लेकर सीधे कानपुर के लिए रवाना हो गई है, जहाँ साइबर सेल के अधिकारी उससे आगे की पूछताछ करेंगे। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी ने यह टिप्पणी किसी राजनीतिक द्वेष के चलते की थी या इसके पीछे कोई और वजह थी।

जबलपुर में सड़क खराब होने के कारण गर्भवती को 1 किलोमीटर चलना पड़ा पैदल

जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के जबलपुर से सिस्टम की लापरवाही और बदहाल बुनियादी ढांचे की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के ब्रजपुरी कॉलोनी की रहने वाली साढ़े सात महीने की गर्भवती महिला ममता कुशवाहा और उनके अजन्मे बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार शाम को ममता को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुआ था। घर तक जाने वाली सड़क इतनी ज्यादा खराब और जर्जर थी कि कोई भी वाहन चालक उस इलाके के अंदर आने को तैयार नहीं हुआ।

मजबूरन महिला को मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए लगभग एक किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ी, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई।

इलाज के दौरान मां और अजन्मे बच्चे की मौत

मुख्य सड़क से ऑटो से पहुंचीं अस्पताल

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवीन कोठारी के मुताबिक, घर से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। इस वजह से वहां मौजूद आशा कार्यकर्ता ममता को पैदल ही एक किलोमीटर तक लेकर आई। इसके बाद मुख्य सड़क से उन्हें एक किराए के ऑटो-रिक्शा के जरिए एल्गिन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर ममता की स्थिति काफी गंभीर हो गई और उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी। डॉक्टरों ने नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। हालांकि, तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर मां और बच्चे दोनों को नहीं बचा सके।

इस दुखद घटना से जुड़े मुख्य पहलू

- स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, ममता ने उस महीने में दो बार प्रसव पूर्व (एंटीनेटल) जांच कराई थी।
- ममता कुछ समय सतना में रही थीं, जिसके कारण उनके गर्भावस्था पंजीकरण में करीब चार महीने की देरी हुई थी।
- शुरुआती जांच में आपातकालीन प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात सामने आ रही है, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है।
- नियमों के मुताबिक, आशा कार्यकर्ता को खुद वाहन बुक करने के बजाय सीधे 108 एम्बुलेंस सेवा से संपर्क करना चाहिए था।

लापरवाही पर जांच के सख्त आदेश

इस पूरी घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएमएचओ नवीन कोठारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत और उच्च स्तरीय जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या समय पर सही आपातकालीन मदद न मिलने के कारण महिला की स्थिति बिगड़ी। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद जो भी कर्मचारी या अधिकारी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।